लखनऊ

शनिवार, 4 जुलाई, 2026

वर्ष : 11 । अंक: 306

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हर बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि हर बच्चे को सीखने की इच्छा दी जानी चाहिए। – जॉन लुबॉक

TODAY WEATHER

DAY 41° Hi

NIGHT 29° Low

संक्षेप

अदाणी ग्रुप पर निवेशकों का बढ़ा भरोसा, एईएल क्यूआईपी को मिला 38,000 करोड़ रुपये का जबरदस्त रिस्पॉन्स

अहमदाबाद। अदाणी ग्रुप वैश्विक संस्थागत निवेशकों और भारत के बड़े म्यूचुअल फंड्स को आकर्षित करने में सफल रहा है और यह ग्रुप को लेकर निवेशकों के सेंटीमेंट में स्पष्ट बदलाव को दिखाता है। अदाणी ग्रुप की मुख्य कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एआईएल) बीते एक वर्ष में निवेशकों से फ्रैश इक्विटी के जरिए करीब 40,000 करोड़ रुपए जुटाने सफल रही है। वहीं, कई बड़े वैश्विक और घरेलू निवेशकों ने समूह की कई सूचीबद्ध कंपनियों में हिस्सेदारी को बढ़ाया है। अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) ने इस हफ्ते अपने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) का साइज बढ़ाकर 15,000 करोड़ रुपए कर दिया था। कंपनी को इसके लिए लगभग 38,000 करोड़ रुपए की बोलियां मिलीं, जो बेस इश्यू साइज का 3.8 गुना है। यह फंड जुटाने की प्रक्रिया कंपनी के 25,000 करोड़ रुपए के राइट्स इश्यू के एक साल से भी कम समय में हुई है, जिससे पिछले एक साल में जुटाई गई कुल इक्विटी कैपिटल लगभग 40,000 करोड़ रुपए हो गई है। ताजा फंड जुटाने की प्रक्रिया में कई बड़े संस्थागत निवशकों ने भाग लिया, जिनमें कैपिटल ग्रुप, गोल्डमैन सैश, ब्लैकरॉक, ब्लैकस्टोन और नोमुरा शामिल हैं। घरेलू स्तर पर भी बड़ी संख्या में निवेशकों ने भाग लिया। इसमें एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड और टाटा म्यूचुअल फंड शामिल थे।

मस्तक पर श्रीराम का नाम, वैष्णव तिलक संग बाबा महाकाल की दिव्य भस्म आरती

उज्जैन। श्री महाकालेश्वर मंदिर में आषाढ़ कृष्ण पक्ष तृतीया के अवसर पर शुक्रवार को बाबा महाकाल की भव्य भस्म आरती की गई। इस अलौकिक दृश्य के साक्षी बनने के लिए मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। भक्तों ने देर रात से ही कतारबद्ध होकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। शुक्रवार तड़के भगवान वीरभद्र की आज्ञा लेने के बाद ढोल-नगाड़ों के साथ बाबा महाकाल के कपाट खोले गए। दिव्य शृंगार और भस्म आरती के बाद जैसे ही श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन हुए, पूरा मंदिर परिसर जय श्री महाकाल के उद्घोष से गूंज उठा। मंदिर परिसर घंटियों, शंखध्वनि और मंत्रोच्चार से गुंजायमान हो उठा। महाकाल मंदिर के पट खुलने के साथ ही मंत्रोच्चार के बीच भगवान महाकाल का जलाभिषेक कर दूध, दही, घी, शक्कर और फलों के रस से बने पंचामृत से अभिषेक किया गया। बाबा महाकाल को हरि ओम का जल अर्पित किया गया। बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया गया। बाबा के मस्तक पर श्री राम का नाम और वैष्णव तिलक लगाया गया। भस्म आरती में दिव्य शृंगार किया गया। महाकाल मंदिर के पुजारी ने महाआरती संपन्न कराई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल की भस्म आरती के दर्शन किए। अपने आराध्य देव के दर्शन पाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु बीती रात से ही बाबा के दर्शन करने के लिए लाइन में खड़े रहे। जानकारी के मुताबिक, पहले महाकाल को शमशान की राख अर्पित की जाती थी, लेकिन अब विशेष रूप से कपिला गाय के गोबर और औषधीय जड़ी-बूटियों से तैयार भस्म का उपयोग होता है।

मंदिर चढ़ावा चोरी पर संघ ने जारी किया बयान, कहा- चोरी की घटना से राम भक्तों की श्रद्धा को आघात पहुंचा

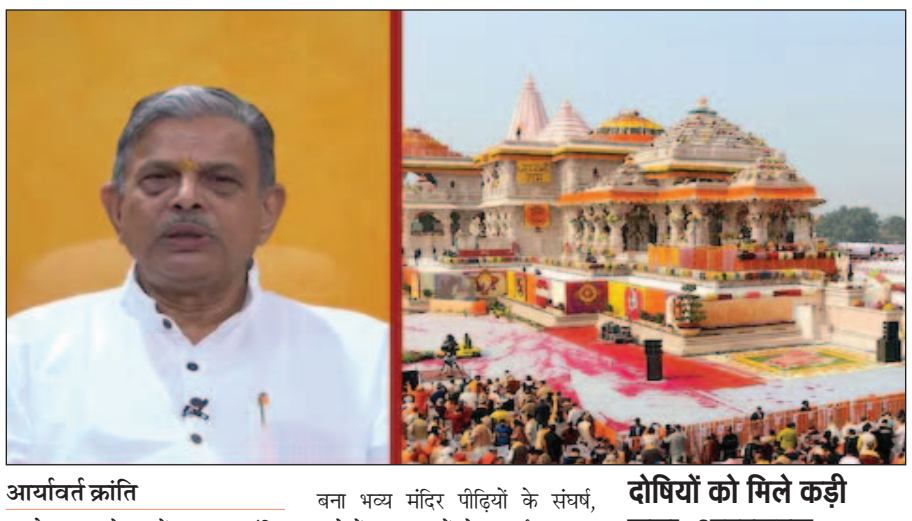

आर्यावर्त क्रांति

अयोध्या। अयोध्या में रामलला मंदिर चढ़ावा चोरी होने की घटना पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने कड़ा बयान जारी किया। संघ ने कहा कि यह घटना केवल चोरी का मामला नहीं है, बल्कि इससे करोड़ों राम भक्तों की आस्था और श्रद्धा को गहरा आघात पहुंचा है। संघ ने दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए मंदिर प्रबंधन और व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दिया है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने जारी बयान में कहा कि श्री राम जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर पीढ़ियों के संघर्ष, करोड़ों राम भक्तों के समर्पण, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। यही कारण है कि यह मंदिर पूरे हिंदू समाज की आस्था, श्रद्धा और भक्ति का प्रमुख केंद्र है। ऐसे में अयोध्या स्थित श्री रामलला मंदिर के दान पात्रों में जमा धनराशि की चोरी की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। संघ ने कहा कि इस घटना से पूरे समाज और राम भक्तों की भावनाएं आहत हुई हैं। इसलिए इस मामले को सामान्य अपराध की तरह नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े गंभीर विषय के रूप में देखा जाना चाहिए।

दोषियों को मिले कड़ी सजा: आरएसएस

संघ सरकार्यवाक दत्तात्रेय होसबले ने कहा, 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रह पूर्वक निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया शुरू की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक ही अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मान कर गंभीरता से व्यवस्था और संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों रामभक्तों की आस्था-श्रद्धा अखंड और अटूट बनी रहे।'

हिंदू समाज से संघ ने क्या अपील की?

अपने बयान के अंत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूरे हिंदू समाज से धैर्य और संयम बनाए रखने की अपील की। संघ ने कहा कि इस कठिन समय में समाज को भावनाओं में बहने के बजाय जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए। साथ ही यह भी कहा कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी शक्तियां हिंदू धर्म तथा समाज को बदनाम करने का प्रयास कर सकती हैं। ऐसे किसी भी षड़यंत्र को विफल करना पूरे समाज की जिम्मेदारी है। संघ ने भरोसा जताया कि निष्पक्ष जांच, पारदर्शी व्यवस्था और प्रभावी सुधारों के जरिए मंदिर की गरिमा, पवित्रता और करोड़ों राम भक्तों की आस्था पहले की तरह अटूट बनी रहेगी।

दोषियों पर क्या कार्रवाई की मांग की गई?

संघ ने अपने बयान में कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रह पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। जांच दल की सिफारिश के आधार पर कानूनी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। संघ ने स्पष्ट कहा कि जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाए, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया कि न्याय तभी पूरा माना जाएगा, जब दोषियों को कानून के अनुसार सख्त दंड मिलेगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

मंदिर प्रबंधन से संघ की क्या अपेक्षा है?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा कि इस घटना को असाधारण मानते हुए मंदिर प्रबंधन को व्यवस्था और संचालन की सभी कमियों को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। संघ के अनुसार वर्तमान में जो भ्रम और असमंजस की स्थिति बनी है, उसे जल्द समाप्त करना जरूरी है। इसके लिए मंदिर प्रबंधन और शासन द्वारा गठित विशेष जांच दल आवश्यक पहल करें। संघ ने विश्वास जताया कि बेहतर वित्तीय प्रबंधन, पूरी पारदर्शिता, मजबूत निगरानी व्यवस्था और धार्मिक पवित्रता के वातावरण के जरिए श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास करोड़ों श्रद्धालुओं का विश्वास और अधिक मजबूत करेगा।

पहचान के संकट से निकलकर पीएम बना देश की टॉप थ्री इकोनॉमी : सीएम योगी का दावा

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि पिछले नौ सालों में राज्य ने 'बीमारू' राज्यों की श्रेणी से निकलकर भारत की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने का सफर तय किया है। उन्होंने इस बदलाव का श्रेय अच्छे शासन, टीम वर्क और टेक्नोलॉजी के प्रभावी इस्तेमाल को दिया। डॉ. राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी के नए अत्याधुनिक परिसर के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में राज्य की विकास यात्रा शासन और लोगों की सोच में आए बदलाव को दर्शाती है।

उन्होंने कहा कि पिछले नौ सालों में, उत्तर प्रदेश उस पहचान के संकट से बाहर निकल आया है जिसका सामना उसे कभी करना पड़ा था। आज राज्य ने खुद को उन राज्यों की श्रेणी में स्थापित कर लिया है, जहाँ न तो सरकार, न ही प्रशासनिक तंत्र और न ही जनता को पहचान के संकट का सामना करना पड़ता है। राज्य की आर्थिक प्रगति का ज़िक्र करते हुए CM योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे पिछड़ी पाँच अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी से निकलकर शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। इसने 'बीमारू' राज्य के ठप्पे से मुक्ति पाई है, सुरक्षा और सुशासन के नए मानक स्थापित किए हैं, भीड़-भाड़ के प्रभावी प्रबंधन का उदाहरण पेश किया है और यह दिखाया है कि तकनीक किस तरह आम नागरिकों के जीवन को बदल सकती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन का स्वरूप न केवल राजनीतिक नेतृत्व से, बल्कि प्रशासनिक तंत्र के कामकाज से भी तय होता है। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार के बारे में जनता की राय प्रशासनिक तंत्र के कामकाज से बनती है। नौकरशाही सरकार और जनता के बीच एक पुल का काम करती है। जब यह पुल प्रभावी ढंग से काम करता है, तो सरकारी योजनाएं लाभार्थियों तक पहुंचती हैं और लोगों की सोच बदलती है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) में सुधारों का ज़िक्र करते हुए, CM योगी ने कहा कि 2017 से पहले राशन वितरण को लेकर शिकायतें आम थीं, लेकिन e-PoS मशीनें आने के बाद इनमें काफ़ी कमी आई। उन्होंने कहा कि हमने e-PoS मशीनें लगाईं और शिकायतें बंद हो गईं। टेक्नोलॉजी ने आम आदमी की समस्या का समाधान किया। आज गरीबों को उनका राशन मिल रहा है और सिस्टम में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगी है। टीमवर्क के महत्व पर ज़ोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि टीमवर्क और सकारात्मक सोच ही हमें सफलता दिलाएगी। अगर हम अकेले काम करेंगे, टीम भावना को खत्म करेंगे या दूसरों के प्रति नकारात्मक सोच रखेंगे, तो हम नतीजे नहीं दे पाएंगे।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बड़ा फैसला! दिल्ली के भविष्य के लिए 'स्वच्छ हवा, स्वस्थ दिल्ली' प्रोजेक्ट लॉन्च

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 'स्वच्छ हवा, स्वस्थ दिल्ली' प्रोजेक्ट की शुरुआत की घोषणा की। यह सात साल का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका मकसद वायु प्रदूषण को कम करना है और इसे वर्ल्ड बैंक से आर्थिक मदद मिल रही है। इस प्रोजेक्ट का मकसद दिल्ली के वायु प्रदूषण को कम करने की योजना में तेज़ी लाना, 'नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम' के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना और 'विकसित भारत 2047' के विज़न में योगदान देना है। सितंबर 2026 से अगस्त 2033 तक सभी ज़िलों में लागू होने वाले इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 8,300 करोड़ रुपये है। वर्ल्ड बैंक 65 प्रतिशत फ़ंड देगा, जबकि दिल्ली सरकार बाकी 35 प्रतिशत का खर्च उठाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 10 जुलाई को होने वाली वर्कशॉप में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा और सभी संबंधित पक्षों के बीच तालमेल बिठाया जाएगा। इस वर्कशॉप में अलग-अलग सरकारी विभागों, मुख्य एजेंसियों और वर्ल्ड बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल होंगे, ताकि सबकी भूमिकाएं स्पष्ट की जा सकें और प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए रोडमैप तैयार किया जा सके। इस पहल में प्रदूषण के मुख्य स्रोतों पर ध्यान दिया जाएगा, जैसे कि ट्रांसपोर्ट से निकलने वाला धुआं, सड़क की धूल, निर्माण और तोड़-फोड़ से निकलने वाला कचरा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उद्योगों से निकलने वाला धुआं, हरियाली और जल प्रदूषण।

शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार को दिया बड़ा झटका, प्राइवेट बिजली कंपनियों के कैग ऑडिट पर लगाई रोक

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार द्वारा तीन प्राइवेट बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के कैग ऑडिट के आदेश पर रोक लगा दी। यह मामला उपभोक्ताओं से वसूले जाने वाले 'रेगुलेटरी एसेट्स' (आरए) के तौर पर वर्षों में जमा हुए भारी-भरकम 38,500 करोड़ रुपये से जुड़ा है।

जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की बेंच ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। बेंच ने कहा कि बिजली रेगुलेटर 'दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन' (डीईआरसी) के कैग को नियुक्त करने के फैसले की कानूनी वैधता पर सवाल उठते हैं, जिन पर न्यायिक निर्णय की जरूरत है। भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार को झटका देते हुए शीर्ष अदालत ने आदेश दिया, अगले आदेश तक ऑडिट के लिए किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की नियुक्ति के संबंध में 'अपेलट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी' (एपटेल) के निर्देश पर रोक रहेगी। इस दौरान कैग भी ऑडिट की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाएगा।

शीर्ष अदालत एपटेल के अप्रैल के फैसले के खिलाफ डीईआरसी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। एपटेल ने अपने फैसले में कहा था कि ऑडिट का काम कैग को सौंपना कानूनी ढांचे के खिलाफ है और रेगुलेटर को ऑडिट के लिए एक स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त करने का निर्देश दिया था। डिस्कॉम को नोटिस जारी करते हुए बेंच ने कहा, ₹यह सिविल अपील सीधे तौर पर इस मुद्दे से जुड़ी है कि क्या डीईआरसी द्वारा कैग के माध्यम से वितरण कंपनियों के ऑडिट की प्रक्रिया शुरू करना कानूनी रूप से सही है। शीर्ष अदालत ने कहा कि 15 जुलाई तक यथास्थिति बनाए रखी जाए। उस दिन डीईआरसी की याचिका पर एक रेगुलर बेंच सुनवाई करेगी, जिसने पिछले साल अगस्त में फैसला सुनाया था।

अरविंद केजरीवाल का आरोप : E20 पेट्रोल जनता पर थोपा, गाड़ियां हो रही हैं खराब, माइलेज भी घटा

नई दिल्ली, एजेंसी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जनता पर जबरदस्ती E20 पेट्रोल थोप रही है। उन्होंने दावा किया कि इससे गाड़ियों को नुकसान हो रहा है और ईंधन की क्षमता (माइलेज) भी कम हो रही है। X पर एक वीडियो पोस्ट शेयर करते हुए केजरीवाल ने कहा कि 20 प्रतिशत इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल को लेकर जनता में काफी गुस्सा है। 30 जून को केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह सिर्फ़ एक प्रयोग है और आगे की कार्रवाई इसके नतीजों पर निर्भर करेगी। जब यह बात मीडिया और अख़बारों में आई, तो केंद्र सरकार पूरी तरह से पीछे हट गई। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ कभी नहीं कहा और यह झूठ है।

उन्होंने सरकार के तरीके पर सवाल उठाते हुए कहा, 'और यह किस तरह का प्रयोग है? आपने सभी लोगों और सभी गाड़ियों के लिए इथेनॉल-मिला हुआ पेट्रोल अनिवार्य कर दिया है, और अब आप कह रहे हैं कि आप 'प्रयोग' कर रहे हैं? क्या आप उन लोगों को मुआवज़ा देंगे जिनकी गाड़ियाँ खराब हो रही हैं?' केजरीवाल ने दावा किया कि इथेनॉल मिलाने की वजह से गाड़ियाँ खराब हो रही हैं और उनके पार्ट्स को नुकसान पहुँच रहा है। उन्होंने कहा कि पूरा देश मोदी सरकार के लिए एक एक्सपेरिमेंटल लैब बन गया है। लोगों पर ज़बरदस्ती E20 पेट्रोल थोपा जा रहा है। इथेनॉल की वजह से लोगों की गाड़ियाँ खराब हो रही हैं, पार्ट्स को नुकसान पहुँच रहा है और माइलेज भी कम हो रहा है। लोग बहुत नाराज़ हैं।

उन्होंने आगे कहा कि अगर लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो आप इसे उन पर क्यों थोप रहे हैं? आप इसे वापस क्यों नहीं ले रहे हैं? जनता ने ही आपको वोट दिया है। उनके वोट का सम्मान करना और उनकी बात सुनना आपका कर्तव्य है। केजरीवाल ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने की योजना की घोषणा की और जनता से सुझाव आमंत्रित किए। उन्होंने कहा कि मैं इस मामले पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखने जा रहा हूं। आप सभी कृपया मुझे डीएम करें और टिप्पणी करके बताएं कि मुझे पत्र में क्या लिखना चाहिए।

पूरे महाराष्ट्र में हॉर्स ट्रेडिंग, आपके खिलाफ एफआईआर है तो पाला बदल लीजिए... बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी

मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए बड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने टिप्पणी की कि पूरे महाराष्ट्र में हॉर्स ट्रेडिंग (विधायकों की खरीद-फरोख्त) चल रही है। कोर्ट ने सत्ताधारी पार्टी की ओर इशारा करते हुए कहा कि कोई भी राजनीतिक नेता वॉशिंग मशीन में शामिल होकर अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों को बंद करवा सकता है।

जस्टिस माधव जामदार, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) के महासचिव सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी (49) द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। चौधरी ने केंद्र सरकार और BJP के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के कारण महाराष्ट्र पुलिस द्वारा उनके खिलाफ जारी किए गए 'एक्सटर्नमेंट ऑर्डर' (राज्य से बाहर निकालने का आदेश) को चुनौती दी थी।

हाई कोर्ट ने और क्या कहा?

क्या सरकार के खिलाफ आवाज उठाना अपराध है या लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा? क्या सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से किसी शख्स को उसके क्षेत्र से बाहर निकाला जा सकता है? ऐसे ही एक मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि केवल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने या नारे लगाने के कारण किसी व्यक्ति को उसके जिले से बाहर नहीं किया जा सकता। दरअसल, एक स्थानीय नेता (सईद अहमद चौधरी) सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें 1 साल के लिए जिले से बाहर कर दिया था। इस मामले में कोर्ट ने इस आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा, नारे लगाना और शांतिपूर्वक विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है। सिर्फ इसी वजह से किसी को सजा नहीं दी जा सकती।

'नागरिकों को सरकार का गुलाम बनाया जा रहा'

49 साल के सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस माधव जे। जामदार की सिंगल-जज बेंच ने पुलिस से पूछा कि क्या सरकार के फैसलों का विरोध करने पर केस दर्ज करके नागरिकों को "सरकार का गुलाम" बनाया जा रहा है और वे विरोध-प्रदर्शन क्यों नहीं कर सकते।सईद ने बताया था कि वह सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) के जनरल सेक्रेटरी हैं और उन्हें एक साल के लिए शहर से बाहर निकाल दिया गया था।

चीन के सामने झुक रही सरकार? : कांग्रेस का दावा– चीनी कंपनियों सरकारी टेंडर में हिस्सा लेने की मिली अनुमति

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पार्टी ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार का चीन के सामने टेकने का सिलसिला जारी है, जिससे देश के उद्योगों को बड़ा नुकसान हो रहा है, खासकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई।

पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक मीडिया रिपोर्ट साझा की। उस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत सरकार ने चीन की उन चार बिजली उपकरण बनाने वाली कंपनियों को अहम सरकारी बिजली परियोजनाओं के टेंडर में हिस्सा लेने की अनुमति दी है, जिनकी फैक्ट्रियां भारत में हैं।

अपने पोस्ट में जयराम रमेश ने कहा, मोदी सरकार का चीन के सामने सोच-समझकर जुकने का सिलसिला जारी है। इसी समय भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जिससे देश के उद्योगों का बड़ा नुकसान हो रहा है, खासकर एमएसएमई। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन की उकसाने वाली गतिविधियां लगातार जारी हैं।

'भारत की जल सुरक्षा को खतरा'

रमेश ने दावा किया कि मेडोग (तिब्बत का दूरदराज क्षेत्र का जिला) में दुनिया की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना का निर्माण जारी है। इससे ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ी भारत की जल सुरक्षा को खतरा हो सकता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि पूर्वी लद्दाख के कई इलाकों में भारत ने अपनी पारंपरिक गश्त और पशु चराने के अधिकार छोड़ दिए हैं। उन्होंने कहा, 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक रूप से चीन को 'क्लीन चिट' दे दी थी। रमेश के अनुसार, यह उस समय हुआ, जब लद्दाख में भारत के 20 बहादुर जवानों का बलिदान हुआ था।

रमेश ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की गतिविधियों में चीन की अहम भूमिका थी। उनके अनुसार, इस बात को उप सेना प्रमुख ने स्वीकार किया था और इसका रिकॉर्ड भी मौजूद है। इसके बावजूद भी सरकार का चीन के सामने झुकना लगातार जारी है।

चोरी ही नहीं वसूली भी करता था टिन्नू यादव, राम मंदिर में वीआईपी दर्शन के नाम पर चला रहा था नेटवर्क

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

अयोध्या। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के दौरान विशेष जांच दल (एसआईटी) के हाथ एक और बड़ा सुराग लगा है। जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू ने अपने साथियों के साथ मिलकर वीआईपी दर्शन के नाम पर संगठित वसूली का नेटवर्क बना रखा था। आरोप है कि ये गिरोह श्रद्धालुओं से लाखों रुपये वसूलता था और हर दिन वसूली गई रकम का आपस में बंटवारा किया जाता था।

सूत्रों के अनुसार, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ने के साथ ही वीआईपी दर्शन के नाम पर अवैध वसूली का यह खेल भी बड़े स्तर पर शुरू हो गया था। एसआईटी की जांच में संकेत मिले हैं कि इस नेटवर्क में केवल गिरफ्तार आरोपी ही नहीं, बल्कि मंदिर के कुछ अन्य कर्मचारी और बाहरी लोग भी शामिल हो सकते हैं।जांच एजेंसियां अब इन सभी की भूमिका की पड़ताल कर रही हैं।

व्यवस्था का किया दुरुपयोग

राम मंदिर में दर्शन की अलग-अलग व्यवस्थाएं हैं। सामान्य श्रद्धालुओं को लंबी कतारों में लगकर दर्शन करने पड़ते हैं, जबकि प्रोटोकॉल के तहत आने वाले विशिष्ट अतिथियों को वीआईपी पास के जरिए कम समय में दर्शन की सुविधा मिलती है। ये पास श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से पूरी तरह निःशुल्क जारी किए जाते हैं। एसआईटी के मुताबिक, इसी व्यवस्था का कुछ लोगों ने कथित तौर पर दुरुपयोग किया। श्रद्धालुओं को जल्द और सहज दर्शन कराने का भरोसा देकर उनसे मोटी रकम वसूली जाती थी। जांच में ये भी सामने आया है कि वसूली का पैसा गिरोह के सदस्यों के बीच नियमित रूप से बांटा जाता था। जांच एजेंसियां अब इस कथित रैकेट से जुड़े वित्तीय लेनदेन, मोबाइल कॉल डिटेल, बैंक खातों और दूसरे डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रही हैं। सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ और कर्मचारियों तथा बाहरी लोगों पर भी शिकंजा कस सकता है।

क्या चंपत राय पर विश्व हिंदू परिषद् करेगा कार्रवाई?

राम मंदिर में दान चोरी मामले में टिन्नू यादव पर भरोसे को तोड़ने का आरोप है। ऐसे पर कई गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं कि यहां पर ऑडिट और निगरानी की जिम्मेदारी की किसकी थी? इस मामले में चंपत राय से भी एसआईटी ने कई घंटों तक पूछताछ की। उन्होंने अपने सिरे से सभी आरोपों को खारिज किया है। इस मामले में VHP के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट आलोक कुमार कहा कि अयोध्या में राम मंदिर में दान की चोरी के लिए विश्व हिंदू परिषद (VHP) जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने कहा कि संगठन अपने वाइस प्रेसिडेंट चंपत राय के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से पहले इस मामले की जांच का इंतजार करेगा। उन्होंने कहा कि मंदिर में हुई लूट बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे दुनिया भर के हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। इसके लिए कोई बहाना बनाने या बचाव करने का सवाल ही नहीं उठता। हम सभी चाहते हैं कि पुलिस और SIT हर पहलू और हर उस व्यक्ति की बहुत बारीकी से जांच करें, जिस पर कोई भी आरोप लगा हो, चाहे वह कोई भी हो।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी : व्हाट्सएप चैट से खुलेंगे आरोपियों के राज, धरी की धरी रह जाएगी सारी 'होशियारी'

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

अयोध्या। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच में पुलिस के हाथ अहम डिजिटल साक्ष्य लगे हैं। जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने गिरफ्तारी से पहले अपने मोबाइल फोन फॉर्मेट कर दिए और व्हाट्सएप चैट, फोटो व वीडियो डिलीट कर दिए, ताकि चोरी से जुड़े सबूत मिटाए जा सकें। हालांकि पुलिस ने सभी मोबाइल फोन कब्जे में लेकर उन्हें फॉरेंसिक जांच के मदद लेगी। अब डिलीट किया गया डेटा रिकवर कर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि चोरी की रकम किस तरह बाहर निकाली जाती थी, किन लोगों के बीच उसका बंटवारा होता था।

सूत्रों के मुताबिक, आरोपियों के मोबाइल की शुरुआती जांच में कई महत्वपूर्ण डिजिटल सुराग मिले हैं। पुलिस का दावा है कि व्हाट्सएप पर चोरी की रकम बाहर निकालने, उसके बंटवारे और आपसी तालमेल को लेकर बातचीत के साक्ष्य मिले हैं। गणना के दौरान खुलकर बातचीत संभव नहीं होने के कारण आरोपी कथित तौर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए एक-दूसरे को निर्देश भेजते थे। अब फोरेंसिक विशेषज्ञ डिलीट की गई चैट, फोटो और वीडियो भी रिकवर करने में जुटे हैं।

जांच में यह भी सामने आया है कि कई मोबाइल फोन से जानबूझकर चैट हिस्ट्री और अन्य डेटा हटाया गया था। पुलिस का मानना है कि रिकवर होने वाला डिजिटल डेटा पूरे चोरी नेटवर्क की परतें खोल सकता है। यही इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य आगे विवेचना और एसआईटी की जांच का महत्वपूर्ण आधार बनेंगे।

पुलिस के हाथ लगे ये सबूत

पुलिस को कुछ ऐसे फोटो और वीडियो भी मिले हैं, जिनमें आरोपी एक साथ पार्टी करते और बड़ी मात्रा में नकदी के साथ दिखाई दे रहे हैं। जांच एजेंसियों को आशंका है कि यह वही रकम हो सकती है, जिसे चढ़ावे से कथित तौर पर निकालने के बाद आपस में बांटा गया था।

उधर, मामले की जांच कर रही एसआईटी लगातार दूसरे दिन भी अयोध्या पहुंची और ट्रस्ट के प्रमुख पदाधिकारियों से कई घंटे तक पूछताछ की। टीम ने चढ़ावे के ऑडिट और वित्तीय रिकॉर्ड से जुड़े दस्तावेज अपने कब्जे में लेकर कई बिंदुओं पर जवाब मांगे। सूत्रों का कहना है कि पूछताछ के दौरान कई सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिले, जिसके बाद जांच का दायरा और बढ़ाने की तैयारी है।

जवाबों से संतुष्ट नहीं है पुलिस

सूत्रों के अनुसार, पूछताछ में ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारी अपनी प्रत्यक्ष भूमिका से इनकार करते हुए जिम्मेदारी टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव पर डाल रहे हैं। हालांकि एसआईटी और स्थानीय पुलिस दोनों ही उनके जवाबों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं और कई बिंदुओं का मिलान डिजिटल साक्ष्यों से किया जा रहा है।

इधर, स्थानीय पुलिस भी अपनी आपराधिक विवेचना तेज कर चुकी है। मंदिर प्रबंधन से जुड़े कर्मचारियों, गणनाकर्मियों, निजी सुरक्षा कर्मियों और अन्य संबंधित लोगों से पूछताछ जारी है। कुछ कर्मचारियों को आरोपी बनाया जा चुका है, जबकि बैंक कर्मियों की भूमिका की भी जांच चल रही है। पुलिस चार्टर्ड अकाउंटेंट और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद से पूरे वित्तीय लेनदेन और डिजिटल रिकॉर्ड का विश्लेषण कर रही है। माना जा रहा है कि डेटा रिकवर होने के बाद इस मामले में कई और लोगों की भूमिका उजागर हो सकती है और जल्द ही नई गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं।

दुधवा की 'दुर्गा' से बिछड़ रही 'भवानी', गोरखपुर में होगा पालन-पोषण, सीएम योगी ने दिया था नाम

आर्यावर्त संवाददाता

लखीमपुर। हिंदी फिल्मों में अक्सर ऐसी कहानियां दिखती हैं, जहां कोई बच्चा अनाथ हो जाता है, फिर किसी को उसका सहारा बनते देखा जाता है। लेकिन दुधवा के जंगलों में एक ऐसी ही कहानी सचमुच जी गई- बस फर्क इतना है कि यहां किरदार इंसान नहीं, हाथी हैं।

बिजनौर के जंगलों से करीब तीन सप्ताह की उम्र में दुधवा लाई गई एक मासूम हथिनी को यहां न सिर्फ नया घर मिला, बल्कि 'दुर्गा' नाम की एक ममतामयी हथिनी ने उसे अपनी संतान की तरह अपनाकर जिंदा रहने का सहारा भी दिया।

अब वही हथिनी, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुधवा आकर 'भवानी' नाम दिया था, एक बार फिर प्रशासनिक फैसलों और विभागीय दांव-पेच के बीच फंस गई है। तैयारी उसे गोरखपुर भेजने की है। सवाल यही है,क्या वहां उसे फिर कोई 'दुर्गा' मिलेगी? यह कहानी सिर्फ एक वन्यजीव के संरक्षण की नहीं, बल्कि उस भावनात्मक रिश्ते की भी है, जो जंगल के भीतर इंसानों से ज्यादा संवेदनशील रूप में पलता है। कुछ वर्ष पहले बिजनौर क्षेत्र में एक हथिनी के बच्चे को मां से बिछुड़ने के बाद बचाया गया था। तब वह इतनी छोटी थी कि अपने दम पर जी पाना लगभग असंभव माना जा रहा था। उसे बेहतर देखभाल और संरक्षण के लिए 13 अक्टूबर 2023 को दुधवा लाया गया।

यहां उसकी हालत नाजुक थी। वनकर्मियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि इतने छोटे हाथी को सिर्फ दूध और दवा से नहीं, बल्कि मातृत्व जैसी सुरक्षा और सामाजिक स्वीकार्यता भी चाहिए थी। तभी दुधवा की हथिनी दुर्गा उसके लिए ढाल बनकर सामने आई।

दुर्गा ने उस नन्ही हथिनी को अपने पास रखा, उसे अपनाया, उसकी हर हरकत पर नजर रखी और एक मां की तरह उसके साथ रही। वनकर्मियों के मुताबिक, दुर्गा का व्यवहार देखकर यह साफ महसूस होता था कि उसने भवानी को केवल झुंड का हिस्सा नहीं माना, बल्कि अपने बच्चे की तरह संरक्षण दिया।

यही वजह रही कि वह मासूम हथिनी धीरे-धीरे संभली, खड़ी हुई, चली, और फिर दुधवा के माहौल में ढलती चली गई। यह रिश्ता इतना अनोखा था कि जब वर्ष 2025 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दुधवा पहुंचे और उन्होंने दुर्गा के स्नेह में पल रही इस हथिनी को देखा, तो उसकी कहानी से प्रभावित होकर उसका नाम 'भवानी' रख दिया।

दुधवा के भीतर यह नाम सिर्फ औपचारिक पहचान नहीं बना, बल्कि उस संघर्ष और पुनर्जन्म की कहानी का प्रतीक बन गया, जिसमें एक अनाथ हथिनी को दूसरा जीवन मिला था। लेकिन अब वही भवानी फिर असमंजस के दौर में खड़ी है।

दुधवा अधिकारियों ने उसके बेहतर देखभाल के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक से कहीं और शिफ्ट करने के लिए 29 जून को पत्र लिखा। हथिनी भवानी की सुरक्षा और बेहतर देखभाल के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक अनुराधा वेमुरी ने उसे गोरखपुर भेजने का निर्देश दिया है।

भवानी को गोरखपुर भेजे जाने की खबर से वन्यजीव प्रेमियों के बीच बेचैनी है। उनका कहना है कि सवाल सिर्फ स्थानांतरण का नहीं, बल्कि उस भावनात्मक और व्यवहारिक ताने-बाने का है, जिसमें भवानी अब तक पली-बढ़ी है।

वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि हाथी बेहद संवेदनशील और सामाजिक प्राणी होते हैं। वे अपने झुंड, माहौल और साथियों से गहरे रिश्ते बनाते हैं। ऐसे में किसी हथिनी को उस परिवेश से अलग करना, जहां वह बचपन से रही हो, उसके व्यवहार और मानसिक स्थिति पर असर डाल सकता है। खासकर तब, जब उसकी शुरुआती जिंदगी ही असुरक्षा और बिछोह से भरी रही हो। भवानी के मामले में चिंता इसलिए भी ज्यादा है, क्योंकि उसकी पहचान दुधवा की उस विरल कहानी से जुड़ी है, जहां एक हथिनी ने दूसरी हथिनी को जीवन दिया।

गाजीपुर में पूर्व प्रधान की हत्या के आरोपित मुख्तार के शूटर ने गवाह के घर की फायरिंग

आर्यावर्त संवाददाता

गाजीपुर। भांवरकोल थाना क्षेत्र के रेड़मार गांव निवासी पूर्व प्रधान व रिटायर शिक्षक बरमेश्वर उपाध्याय की दस साल पहले हुई हत्या में नामजद मुख्तार अंसारी का शूटर रहा अमित राय ने उनके गवाह बेटे पर फायरिंग की। इस फायरिंग में वह बाल-बाल बच गए। पुलिस ने शूटर अमित राय व उसके भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

शूटर अमित राय पर कुल 28 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। किसी जमाने में वह मुख्तार अंसारी का नामी शूटर हुआ करता था। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए पांच टीमें गठित की है। उधर, अमित राय की बहन व भाई ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि पुलिस की टीम ने उसे उठा लिया है। अंदेशा जताया कि उसका एनकाउंटर किया जा सकता है।

21 मई 2016 में रेड़मार गांव के पूर्व प्रधान बरमेश्वर उपाध्याय की गोली मारकर उस समय हत्या कर दी गई थी, जब वह खेत में काम कर रहे थे। वह जोगा के स्कूल में शिक्षक भी थे। हत्या में जोगा निवासी अमित राय आरोपित है। मुकदमा अदालत में विचाराधीन है। उनका पुत्र प्रवीण उपाध्याय शहर के अष्टभुजी कालोनी में रहते हैं।

पीड़ित ने तहरीर देते हुए बताया कि बुधवार की भोर पौने चार बजे दरवाजा खट खटाया गया। दूसरी मंजिल से जब झांककर देखा तो बाइक सवार दो लोगों ने उनके ऊपर गोली चलाई। जल्दी से पीछे हटकर बैठा तो मुझे लक्ष्य करके एक फायर और किया गया।

भागकर नीचे जाकर खिड़की से देखा तो गोली चलाने वाले जोगा मुसाहिब निवासी अमित राय व उसका साथी आयुष राय है। दोनों ने धमकी दी कि पिता की हत्या का मुकदमा वापस नहीं लिया तो अंजाम बुरा होगा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से तीन खोखा कारतूस बरामद किया।

प्रदेश में लगातार बढ़ रहे भ्रष्टाचार: राजेंद्र गौतम

जौनपुर। कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी नियुक्त किए जाने के बाद पहली बार जौनपुर पहुंचे राजेंद्र पाल गौतम का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश चुनाव प्रभारी ने उत्तर प्रदेश की मौजूदा भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार इन गंभीर समस्याओं के समाधान के बजाय जनता का ध्यान भटकाने में लगी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कानून-व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है और आम नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है।उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाए गए चंदे को लेकर भी सवाल उठाते हुए कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने पेपर लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और सरकार परीक्षाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करने में विफल रही है।

श्रावस्ती में दो ट्रकों की आमने-सामने टक्कर, दोनों के चालकों की मौत और छह घायल

आर्यावर्त संवाददाता

श्रावस्ती। बौद्ध परिपथ पर शुक्रवार की सुबह दो ट्रकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। नवीन मार्डन क्षेत्र में खरगौराबस्ती विजयीपुरवा गांव के पास हुई दुर्घटना में दोनों ट्रक के चालकों की मौत हो गई।

दो ट्रकों की आमने-सामने टक्कर में खलासी व सड़क किनारे घर के सामने बेटे के साथ सो रहे दंपती समेत छह लोग घायल हो गए। इलाज के लिए इन्हें इकौना सीएचसी पहुंचाया गया। यहां दंपती व खलासी समेत सभी घायलों को मेडिकल कालेज बहराइच के लिए रेफर किया गया है। मृतक चालक सिद्धार्थनगर और बरेली जिले के निवासी हैं।

सिद्धार्थ नगर जिले के खेसराहा क्षेत्र के देवरी गांव निवासी चालक अमजद हुसैन ट्रक पर लकड़ी लादकर संतकबीरनगर के बखिरा क्षेत्र के अमर दोहरा गांव निवासी खलासी नबीउल्ला के साथ बहराइच की ओर जा रहे थे। बरेली जिले के गोता क्षेत्र के गुलरियाजगत गांव निवासी चालक अंशू ट्रक पर कोल्डड्रिंक लादकर बरेली के ही भुता क्षेत्र के मुरादपुर गांव निवासी खलासी गोपी सिंह व सीतपुर जिले के तंबौर निवासी मुहम्मद सद्दाम के साथ सिद्धार्थनगर जा रहे थे।

इसी दौरान नवीन माडर्न श्रावस्ती क्षेत्र के खरगौरा बस्ती विजयीपुरवा गांव के निकट बौद्ध परिपथ पर दोनों ट्रकों की आमने-सामने से टक्कर हो गई। दुर्घटना होते ही ट्रक पर लदे लकड़ी के बोटे गिरने लगे। इससे घर के सामने चारपाई पर सो रहे विजयीपुरवा गांव निवासी अरुण कुमार पांडेय उर्फ पिंटू व उनकी पत्नी सीमा पांडेय और 13 वर्षीय बेटा पीयूष पांडेय गंभीर रूप से घायल हो गए।

हादसे में एक ट्रक के चालक अंशु की मौके पर मौत हो गई, जबकि खलासी गोपी सिंह, मुहम्मद सद्दाम व दूसरे ट्रक चालक अमजद हुसैन व खलासी नबीउल्लाह गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने इलाज के लिए इन्हें इकौना सीएचसी पहुंचाया। यहां चिकित्सकों ने ट्रक चालक अमजद को भी मृत घोषित कर दिया। अन्य घायलों को मेडिकल कालेज बहराइच के लिए रेफर किया गया है। पुलिस घटना के कारणों के पड़ताल में जुटी है।

38 हजार की बाइक पर 1.5 लाख का जुर्माना... 156 बार कटा चालान, अब क्या होगा एक्शन?

आर्यावर्त संवाददाता

आगरा। उत्तर प्रदेश के आगरा उत्तर प्रदेश के ताजनगरी आगरा से ट्रैफिक नियमों की अनदेखी और कानून का मखौल उड़ाने का एक बेहद अजब-गजब मामला सामने आया है। यहां एक रसूखदार और बेखौफ बाइक चालक पर यातायात नियमों के उल्लंघन के चलते करीब डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लग चुका है, जबकि उसकी बाइक की मौजूदा बाजार कीमत महज 38 हजार रुपये है। यानी बाइक की असली कीमत से चार गुना से ज्यादा का तो सिर्फ चालान काटा जा चुका है।

यह मामला साफ तौर पर दर्शाता है कि सड़कों पर लगे कैमरे तो मुस्तैदी से अपना काम करते रहे, लेकिन वाहन चालक बिना किसी डर के नियमों की धज्जियां उड़ाता रहा। अब ऐसे आदतन यातायात नियम तोड़ने वाले अभ्यस्त अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए प्रशासन ने बेहद सख्त रूप अख्तियार कर लिया है।

मिली जानकारी के मुताबिक, पिछले पांच सालों (2021 से 2026) के दौरान इस दोपहिया वाहन के कुल 156 चालान काटे गए हैं। ये सभी चालान शहर के प्रमुख चौराहों पर लगे ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरों के जरिए ऑनलाइन दर्ज हुए हैं। ये कैमरे बिना किसी पुलिसकर्मी की मौके पर मौजूदगी के रेड लाइट जंप करने, जेब्रा क्रॉसिंग पार करने और बिना हेलमेट गाड़ी चलाने जैसी गलतियों पर सीधे परिवहन विभाग के सर्वर से चालान जनरेट कर देते हैं।

क्या बोले ARTO विनय सिंह?

एआरटीओ (ARTO) विनय कुमार सिंह ने बताया कि ये चालान पूरी तरह से डिजिटल होते हैं और वाहन स्वामी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर केवल एक एसएमएस (SMS) भेजा जाता है। कई रसूखदार या लापरवाह वाहन चालक इन संदेशों को नजरअंदाज कर गाड़ी सड़कों पर दौड़ाते रहते हैं। जब तक पुलिस मौके पर गाड़ी रोककर जांच नहीं करती, तब तक कैमरे हर बार नियम तोड़ने पर जुर्माना जोड़ते चले जाते हैं।

654 वाहनों को नोटिस; सीधे दर्ज होगी FIR

आगरा जिले में बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों की एक ब्लैक लिस्ट तैयार की गई है, जिसके आंकड़े परिवहन विभाग के अधिकारियों को भी हैरान कर रहे हैं। शहर के कई वाहन चालकों के लिए ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना और नो-पार्किंग में गाड़ी खड़ी करना रोज की आदत बन चुका है।

फिलहाल, प्रशासन ने ऐसे 654 वाहनों को चिन्हित कर उनके रजिस्ट्रेशन निरस्तीकरण (निरस्त करने) का अंतिम नोटिस भेज दिया है। एआरटीओ प्रशासन विनय कुमार सिंह के अनुसार, यदि तय समय के भीतर वाहन स्वामियों ने अपने लंबित चालानों का भुगतान नहीं किया, तो वाहनों का रजिस्ट्रेशन हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके बाद भी यदि गाड़ियां सड़क पर चलती मिलीं, तो उन्हें तुरंत जब्त करने के साथ-साथ वाहन मालिकों पर जालसाजी और कानून के उल्लंघन की गंभीर धाराओं में सीधे एफआईआर (FIR) दर्ज कराई जाएगी।

आखिर कैसे तय होती है पुरानी गाड़ी की कीमत?

परिवहन विभाग या पुलिस विभाग किसी भी पुरानी गाड़ी की कीमत अपने मन से तय नहीं करता। इसके लिए एक वैज्ञानिक और कानूनी तरीका अपनाया जाता है, जिसे इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू (IDV) कहा जाता है। शोरूम से बाहर निकलने के बाद समय के साथ वाहन में होने वाली घिसावट के कारण उसकी कीमत घटने लगती है। भारतीय कानून के अनुसार, गाड़ी की उम्र के आधार पर उसकी आईडीवी तय की जाती है, जिसके तहत ही इस पैशन प्रो बाइक की वैल्यू 38 हजार रुपये आंकी गई है।

'मिशन सेफ फ्यूचर', स्कूल वाहनों की होगी जांच

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। जिले में स्कूली बच्चों की सुरक्षा और सुरक्षित परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग 1 से 15 जुलाई तक विशेष अभियान 'मिशन सेफ फ्यूचर' चलाएगा। अभियान के तहत जनपद में संचालित सभी स्कूल वाहनों की सघन जांच की जाएगी। बिना फिटनेस, परमिट अथवा सुरक्षा मानकों का पालन किए बिना संचालित वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि संभागीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) अजीत सिंह ने सभी विद्यालय प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों से अपील की है कि वे 7 जुलाई तक अपने विद्यालयों में संचालित सभी वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट, बीमा सहित अन्य आवश्यक अभिलेखों को नियमानुसार अद्यतन करा लें। उन्होंने अभिभावकों से भी बच्चों को स्कूल ले जाने वाले वाहनों के सुरक्षा मानकों की जानकारी रखने और केवल मानक पूरे करने वाले वाहनों का ही उपयोग सुनिश्चित करने की अपील की।आरटीओ ने बताया कि 7 जुलाई के बाद परिवहन विभाग, पुलिस और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम विशेष प्रवर्तन अभियान चलाकर स्कूल वाहनों की जांच करेगी। जांच के दौरान बिना परमिट, बिना फिटनेस या निर्धारित सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करते पाए जाने वाले वाहनों के खिलाफ चालान, सीज सहित अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने चेतावनी दी कि बार-बार निर्देश और चेतावनी के बावजूद यदि कोई विद्यालय बिना फिटनेस और परमिट वाले वाहनों का संचालन करता पाया गया, तो ऐसे विद्यालयों की सूची तैयार कर संबंधित सक्षम अधिकारियों को भेजी जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित विद्यालय की मान्यता निरस्त कराने की भी कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने किया नौवें आम महोत्सव का उद्घाटन, 800 से अधिक किस्मों के आम बने आकर्षण का केंद्र

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित नौवें तीन दिवसीय आम महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने 'आम महोत्सव-2026' की स्मारिका का विमोचन किया तथा प्रगतिशील बागवानों को सम्मानित किया।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने महोत्सव के आयोजन में मुख्यमंत्री के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष महोत्सव में 800 से अधिक किस्मों के आम प्रदर्शित किए गए हैं, जो बच्चों, युवाओं और आम प्रेमियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र हैं।उन्होंने बताया कि महोत्सव का आयोजन तीन स्थानों पर किया गया है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आम प्रदर्शनी, मलिहाबाद के बागों में किसानों के साथ संवाद तथा जनभवन में राज्यपाल की उपस्थिति में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसका उद्देश्य बागवानी को बढ़ावा देना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। उद्यान मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार बागवानी क्षेत्र में लगातार नवाचार कर रही है। आम की गुणवत्ता सुधारने के लिए पेपर बैग तकनीक को बढ़ावा दिया गया है। इसके साथ ही कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड का गठन, उच्च तकनीक पौधशालाओं की स्थापना तथा कमल की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने जैसे अनेक कदम उठाए गए हैं।उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में उच्च तकनीक पौधशालाओं के माध्यम से वितरित किए जाने वाले पौधों की संख्या 74 लाख से बढ़कर 29 करोड़ तक पहुंच गई है। शहरी क्षेत्रों में छत पर बागवानी को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे हरित वातावरण विकसित होगा और कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण में सहायता मिलेगी।दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री राज्य औद्यानिक विकास योजना तथा मंडल स्तर पर आयोजित उन्नयन गोष्ठियों के माध्यम से औषधीय, फल एवं उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की मात्र 9 प्रतिशत कृषि भूमि पर होने वाली बागवानी फसलों का कृषि उत्पादन में 42 प्रतिशत योगदान है, जबकि 91 प्रतिशत भूमि पर पारंपरिक कृषि का योगदान 58 प्रतिशत है। यह बागवानी क्षेत्र की बढ़ती उत्पादकता का प्रमाण है।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के आम सहित विभिन्न उद्यानिकी उत्पाद अब अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया, सिंगापुर, कुवैत, न्यूजीलैंड, बेल्जियम, जापान, इटली, कतर, रूस, जर्मनी, मॉरीशस, नीदरलैंड, ओमान, नेपाल, थाईलैंड, बहरीन और स्वीडन सहित अनेक देशों में निर्यात किए जा रहे हैं।उद्यान मंत्री ने बताया कि आम और शहद उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी है। प्रदेश के शहद को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए 'काशी शहद' के नाम से उसका ब्रांड विकसित किया गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में नौवें तीन दिवसीय आम महोत्सव का उद्घाटन किया और 'आम महोत्सव 2026' की स्मारिका का विमोचन किया

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार और कृषि निर्यात राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने महोत्सव के सफल आयोजन में मुख्यमंत्री के सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया।उद्यान मंत्री ने बताया कि इस महोत्सव में 800 से अधिक प्रकार के आम प्रदर्शित किए गए, जो बच्चों और अभिभावकों के लिए एक अनूठा अनुभव प्रदान करते हैं।यह महोत्सव तीन स्थानों पर आयोजित किया गया: इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, मलिहाबाद के बागानों में किसानों के साथ, और जनभवन में राज्यपाल के साथ, जिसका उद्देश्य राज्य के किसानों की समृद्धि और खुशहाली को बढ़ावा देना है।उद्यान विभाग द्वारा किए गए नवाचारों में आम की गुणवत्ता सुधारने के लिए पेपर बैग तकनीक का उपयोग, निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड का गठन, हाई-टेक नर्सरी की स्थापना, और कमल की खेती को बढ़ावा देना शामिल है।उद्यान मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हाई-टेक नर्सरी के माध्यम से दिए जाने वाले पौधों की संख्या 74 लाख से बढ़कर 29 करोड़ हो गई है।शहरी क्षेत्रों में छत पर बागवानी (रूफ टॉप गार्डनिंग) को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है, जो शहरों में घटती कृषि भूमि के बीच सकारात्मक ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण में मदद करेगा।मुख्यमंत्री राज्य औद्यानिक विकास योजना' और मंडल स्तर पर औद्योगिक उन्नयन गोष्ठियां आयोजित की गईं, जिससे कम क्षेत्रफल में अधिक मूल्य की फसलों, जैसे औषधीय फसलों, को बढ़ावा मिल सके।उद्यान विभाग की मेहनत और प्रयासों के कारण, राज्य की 9% भूमि पर औद्यानिक फसलों का उत्पादन 42% तक पहुँच गया है, जबकि कृषि विभाग की 91% भूमि पर 58% की हिस्सेदारी है।उत्तर प्रदेश के औद्यानिक उत्पाद अमेरिका, ब्रिटेन, अरब, मलेशिया, सिंगापुर, कुवैत, न्यूजीलैंड, बेल्जियम, जापान, इटली, कतर, रूस, जर्मनी, मॉरीशस, नीदरलैंड, ओमान, नेपाल, थाईलैंड, बहरीन और स्वीडन जैसे देशों तक पहुँच रहे हैं। भारत में आम और शहद के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक उपज देता है। शहद की ब्रांडिंग 'काशी शहद' के नाम से की गई है, जिसका लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाना है। मखाना, खजूर, कमल, स्ट्रॉबेरी और ड्रैगन फ्रूट जैसी फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए भी नवाचार किए गए हैं।उद्यान मंत्री ने उद्यान विभाग के 50 वर्षों के इतिहास में वर्तमान स्थिति पर गर्व व्यक्त किया और कहा कि विभाग ने किसानों और सरकार दोनों का सम्मान बढ़ाया है।लखनऊ के अलीगंज में हुई एक दुखद घटना के कारण सांस्कृतिक कार्यक्रमों को रद्द करने का निर्णय लिया गया, जो भारतीय संस्कार संस्कृति का हिस्सा था।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दो दिवसीय संगठनात्मक दौरे पर आएंगे उत्तर प्रदेश

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 4 और 5 जुलाई को उत्तर प्रदेश के दो दिवसीय संगठनात्मक दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठक कर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। प्रदेश भाजपा की नई टीम के गठन के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह पहला उत्तर प्रदेश दौरा होगा।प्रदेश भाजपा के अनुसार, नितिन नवीन शनिवार को पूर्वाह्न 11 बजे चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे, जहां पार्टी कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद उनका काफिला आलमबाग, टी.एन. चतुर्वेदी चौराहा, चारबाग, दीनदयाल स्मृतिका, महाराणा प्रताप चौराहा और बलिंगटन चौराहा होते हुए प्रदेश भाजपा मुख्यालय पहुंचेगा। मार्ग में विभिन्न स्थानों पर कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा।प्रदेश मुख्यालय पहुंचने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश पदाधिकारियों, क्षेत्रीय अध्यक्षों, प्रदेश मोर्चा अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों के साथ संगठनात्मक बैठक करेंगे। इसके बाद वह पुराना हैदराबाद स्थित हनुमान सेतु मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे।दोपहर बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उपमुख्यमंत्रियों, भाजपा सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। इसके उपरांत प्रदेश भाजपा की कोर समिति के साथ भी संगठनात्मक चर्चा करेंगे।शाम को नितिन नवीन पद्मश्री सम्मान से सम्मानित डॉ. विद्या बिंदु सिंह के आवास पर विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ रात्रिभोज करेंगे।दौरे के दूसरे दिन रविवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ चाय पर संवाद करेंगे। इसके बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं के साथ संयुक्त बैठक करेंगे। वह उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से अलग-अलग मुलाकात कर संगठनात्मक एवं राजनीतिक विषयों पर चर्चा करेंगे।दोपहर में नितिन नवीन राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद वह लखनऊ के पीर नगर क्षेत्र में बूथ अध्यक्ष शिवाजी रावत के आवास पर पहुंचकर बूथ स्तर पर संगठन की गतिविधियों और आगामी कार्यक्रमों की जानकारी लेंगे।भाजपा के अनुसार, यह दौरा संगठन को और अधिक मजबूत बनाने, बूथ स्तर तक पार्टी की सक्रियता बढ़ाने तथा वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की रणनीति को अंतिम रूप देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

बर्खास्त विद्युत कर्मचारी को उच्च न्यायालय से अंतरिम राहत

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) से बर्खास्त कर्मचारी राघवेन्द्र प्रताप को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ से राहत मिली है। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं अन्य प्रतिवादियों को चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।यह मामला रिट-ए संख्या 5375/2026 (राघवेन्द्र प्रताप बनाम उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं अन्य) से संबंधित है, जिसकी सुनवाई न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा की एकल पीठ ने की।याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता उपेन्द्र कुमार सागर, कौशेन्द्र प्रताप सिंह और प्रताप सिंह ने पक्ष रखा, जबकि प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता मनीष जौहरी एवं आलोक सारन उपस्थित रहे। याचिका में 23 जून 2025 तथा 15 अप्रैल 2026 को जारी बर्खास्तगी आदेशों को चुनौती देते हुए उन्हें निरस्त किए जाने की मांग की गई है।

व्यापारियों का उत्पीड़न स्वीकार नहीं, नियमों के पालन के लिए तीन माह का समय दे प्रशासन : रोहित अग्रवाल

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित अग्रवाल ने लखनऊ में अग्निशमन विभाग और लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर की जा रही कार्रवाई पर चिंता जताते हुए कहा कि जनसुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन प्रत्येक व्यापारी की जिम्मेदारी है और व्यापारिक समाज इसका पूर्ण समर्थन करता है। लेकिन नियमों के अनुपालन के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता।उन्होंने कहा कि किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान को स्थापित करने में वर्षों की मेहनत, जीवन भर की पूंजी और अनेक परिवारों की आजीविका जुड़ी होती है। ऐसे में बिना पर्याप्त समय दिए अचानक कठोर कार्रवाई करना उचित नहीं है। प्रशासन को दंडात्मक के बजाय सहयोगात्मक और समाधानपरक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।रोहित अग्रवाल ने कहा कि यदि वर्षों पहले हुए निर्माण में किसी प्रकार की अनियमितता रह गई है तो उसका पूरा दोष केवल व्यापारी पर नहीं डाला जा सकता। निर्माण के समय संबंधित विभागों की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। यदि वर्षों तक अनुमति देने वाले विभाग आज अचानक पूरे शहर के निर्माण को अवैध बताने लगें तो इससे व्यापारियों में असुरक्षा और अविश्वास की भावना पैदा होती है।उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार, अग्निशमन विभाग और लखनऊ विकास प्राधिकरण से मांग की कि जिन प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा अथवा अन्य तकनीकी कमियां हैं, उन्हें दूर करने तथा आवश्यक मानचित्र स्वीकृत कराने के लिए कम से कम तीन माह का समय दिया जाए। इस अवधि में व्यापारी आवश्यक सुधार कार्य कराने के लिए पूरा सहयोग करेंगे।रोहित अग्रवाल ने कहा कि व्यापार प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसलिए व्यापारियों को प्रताड़ित करने के बजाय उन्हें नियमों के अनुरूप कार्य करने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए। उन्होंने प्रशासन और व्यापारिक संगठनों के बीच संवाद स्थापित कर ऐसा समाधान निकालने की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे जनसुरक्षा भी सुनिश्चित हो और व्यापार तथा रोजगार भी सुरक्षित रह सकें।

संक्षेप

रहीमाबाद में गोली चलने की सूचना निकली भ्रामक, मोटरसाइकिल फिसलने से युवक हुआ घायल

लखनऊ। रहीमाबाद क्षेत्र के गहदो, पाण्डेय खेड़ा के निकट गोली चलने की सोशल मीडिया पर प्रसारित सूचना पुलिस जांच में भ्रामक पाई गई। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि घटनास्थल से गोली चलने का कोई साक्ष्य या खोखा बरामद नहीं हुआ है।पुलिस के अनुसार, शुक्रवार को सोशल मीडिया के माध्यम से रहीमाबाद क्षेत्र में गोली चलने की सूचना प्राप्त होने पर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और मामले की जांच की।जांच में पता चला कि ग्राम सिसवारा निवासी विवेक पाठक और ग्राम गहदो निवासी मो. समीर के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। विवाद के बाद विवेक पाठक मोटरसाइकिल से वहां से निकल गया, जबकि मो. समीर चार पहिया वाहन से उसका पीछा करने लगा। इसी दौरान विवेक पाठक की मोटरसाइकल अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गिर गई, जिससे उसे चोटें आईं।पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद बताया कि गोली चलने संबंधी कोई साक्ष्य, खोखा अथवा अन्य प्रमाण नहीं मिले हैं। जांच में सोशल मीडिया पर प्रसारित गोली चलने की सूचना पूरी तरह असत्य और भ्रामक पाई गई।पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाकर तहरीर लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्राप्त तहरीर और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है। साथ ही नागरिकों से अपील की है कि अपुष्ट एवं भ्रामक सूचनाओं पर विश्वास न करें और ऐसी अफवाहों का प्रसार करने से बचें।

दुष्कर्म के आरोपित को गोमतीनगर पुलिस ने किया गिरफ्तार

लखनऊ। गोमतीनगर पुलिस ने नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने के आरोप में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में पहले से मुकदमा दर्ज था।पुलिस के अनुसार, 23 मई 2026 को पीड़िता ने गोमतीनगर थाने में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि अभियुक्त ने उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। शिकायत के आधार पर थाना गोमतीनगर में मुकदमा संख्या 196/2026, धारा 64(2) एवं 123 भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर विवेचना वरिष्ठ उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह को सौंपी गई थी।विवेचना के दौरान शुक्रवार को वरिष्ठ उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह एवं उपनिरीक्षक त्रिविक्रम सिंह ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अभिषेक कुमार उर्फ कुमार अभिषेक (46) को आशियाना क्षेत्र स्थित होटल ट्री व्यू रेजीडेंसी से गिरफ्तार कर लिया।गिरफ्तार अभियुक्त गोमतीनगर के विपुल खंड का निवासी है तथा उसका मूल निवास बलिया जनपद के बासडीह रोड थाना क्षेत्र के बहादुरपुर में है।पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है।

गैर-जमानती वारंट का अभियुक्त कैसरबाग पुलिस के हत्थे चढ़ा

लखनऊ। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर अपराधियों एवं न्यायालय से वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत कैसरबाग पुलिस ने गैर-जमानती वारंट के एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है।पुलिस के अनुसार, माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (अष्टम), लखनऊ द्वारा वाद संख्या 77304/209 एवं अपराध संख्या 263/17 में जारी गैर-जमानती वारंट के अनुपालन में अभियुक्त संजय गुप्ता को गिरफ्तार किया गया।गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान संजय गुप्ता (54) पुत्र बनवारी लाल गुप्ता, निवासी बब्लू वाली गली, डालीगंज, थाना हसनगंज, लखनऊ के रूप में हुई है। उसे 2 जुलाई 2026 की रात लगभग 8:45 बजे डालीगंज रेलवे स्टेशन परिसर से गिरफ्तार किया गया।पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।इस कार्रवाई को सहायक पुलिस आयुक्त कैसरबाग एवं प्रभारी निरीक्षक कैसरबाग के निर्देशन में उपनिरीक्षक मोहित कुमार तथा आरक्षी अनीश वर्मा ने अंजाम दिया।

पीएनबी गिल्ट्स ने मनाया 30वां स्थापना दिवस, भारतीय ऋण बाज़ार में तीन दशक के योगदान का किया स्मरण

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। पंजाब नेशनल बैंक की सहायक कंपनी एवं स्वतंत्र प्राथमिक डीलर पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड ने अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर कंपनी ने भारतीय ऋण बाज़ार और सरकारी प्रतिभूति व्यवस्था के विकास में अपने तीन दशकों के योगदान को रेखांकित किया।वर्ष 1996 में स्थापित पीएनबी गिल्ट्स ने सरकारी प्रतिभूतियों, राजकोषीय समाधान, बाज़ार निर्माण, अभिग्रहण तथा ऋण पूंजी बाज़ार सेवाओं के माध्यम से देश के स्थिर आय बाज़ार को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।स्थापना दिवस समारोह में पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अशोक चंद्र, पीएनबी गिल्ट्स के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी पारीद सुनील, निदेशक मंडल के सदस्य, वरिष्ठ प्रबंधन, कर्मचारी तथा अन्य विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे।कंपनी ने बताया कि उसकी कुल निवल संपत्ति लगभग 1,700 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है। ऋण पूंजी बाज़ार कारोबार में पीएनबी गिल्ट्स ने देश के शीर्ष 10 संस्थानों में स्थान बनाया है। साथ ही, कंपनी ने शेयर बाज़ारों में सूचीबद्ध होने के 25 वर्ष भी सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं।वित्त वर्ष 1997 से वित्त वर्ष 2026 के दौरान कंपनी ने अपनी दीर्घकालिक स्वामित्व निधि में लगभग 13 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की है, जो उसकी मजबूत वित्तीय स्थिति और संतुलित विकास को दर्शाती है।इस अवसर पर कहा गया कि पीएनबी गिल्ट्स की 30 वर्षों की यात्रा उत्कृष्ट कार्यप्रणाली, ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण और मजबूत वित्तीय अनुशासन का परिचायक है। कंपनी ने सरकारी प्रतिभूति बाज़ार के विकास, नवाचार, सुदृढ़ प्रशासन, विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन तथा हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।कंपनी ने यह भी बताया कि पिछले वर्षों में उसने प्रौद्योगिकी के उपयोग, प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण, जोखिम प्रबंधन प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने तथा सतत विकास संबंधी पहलों के माध्यम से अपने व्यावसायिक आधार का निरंतर विस्तार किया है।

धारदार हथियार से हमला करके शटरिंग मिस्त्री की हत्या, फोन करके बुलाया; कहासुनी के बीच मार डाला

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को धारदार हथियार और कुल्हाड़ी से हमला करके शटरिंग मिस्त्री की हत्या कर दी गई। घटना से घर में चीख पुकार मच गई। ग्रामीणों के मुताबिक, घटना के दौरान दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई। फायरिंग भी की गई। मौके पर कई बाइक और अन्य वाहन क्षतिग्रस्त मिले हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

घटना पीजीआई थाना क्षेत्र के जगतखेड़ा गांव की है। गांव निवासी अभिषेक रावत की हत्या हुई है। बताया गया कि अभिषेक शटरिंग और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। उसके पिता विनोद रावत की तीन साल पहले मौत हो चुकी है। घर में मां पुष्पा, एक बहन और दो छोटे भाई हैं। परिवार का खर्च अभिषेक ही उठाता था।

मां पुष्पा ने बताया कि शुक्रवार दोपहर करीब 3.30 बजे अभिषेक को फोन करके सरथुआ बुलाया गया था। वहां पहले से मौजूद आधा दर्जन से अधिक लोगों ने उस पर धारदार हथियार और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। लेकिन, तब तक हमलावर भाग गए थे।

एसीपी गोसाईगंज ऋषभ यादव ने बताया कि अभिषेक पर धारदार हथियार से हमला किया गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मुकदमा दर्ज करके आरोपियों की तलाश की जा रही है।

यूपी में लगातार सातवें साल नहीं बढ़ीं बिजली दरें, मंत्री शर्मा बोले- देश में सबसे बेहतर बिजली आपूर्ति

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि प्रदेश में लगातार सातवें वर्ष भी बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल है, जहां बिजली की दरें सबसे कम हैं और विद्युत आपूर्ति सबसे बेहतर श्रेणी की है। शुक्रवार को लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में ऊर्जा मंत्री ने बताया कि सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए बिजली का टैरिफ यथावत रखा गया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय सरकार की जनकल्याणकारी नीति और गरीबों, किसानों, घरेलू एवं अन्य उपभोक्ताओं के हितों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। प्रदेश ने 32,673 मेगावाट की अब तक की सर्वाधिक बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने कहा कि बेहतर विद्युत प्रबंधन और मजबूत बुनियादी ढांचे के कारण प्रदेश की बिजली व्यवस्था लगातार सुदृढ़ हो रही है।

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) चार्जिंग और सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक निर्धारित सोलर आवर्स में बिजली दरों पर 20 प्रतिशत की टैरिफ छूट लागू की गई है। इससे हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और ईवी चार्जिंग को भी प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में जितनी बिजली तापीय स्रोतों से बनती थी, उससे अधिक उत्पादन अब सौर ऊर्जा से किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने जारी किया 501 पृष्ठों का टैरिफ आदेश

वर्ष 2026-27 की बिजली दरों और वितरण कंपनियों की वित्तीय व्यवस्था को दी मंजूरी

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने राज्य की सभी प्रमुख विद्युत वितरण कंपनियों के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक राजस्व आवश्यकता, बिजली दरों तथा वित्तीय प्रबंधन से संबंधित विस्तृत आदेश जारी कर दिया है। 501 पृष्ठों के इस आदेश में वर्ष 2024-25 के शुल्क समायोजन, वर्ष 2025-26 की वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा तथा वर्ष 2026-27 के लिए नई राजस्व आवश्यकता और विद्युत दरों को स्वीकृति प्रदान की गई है।आयोग ने यह आदेश विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 एवं 64 के अंतर्गत जारी किया है। यह आदेश दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (आगरा), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (लखनऊ), पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (मेरठ), पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (वाराणसी) तथा कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड की ओर से प्रस्तुत याचिकाओं पर सुनवाई के बाद पारित किया गया।

आदेश में वर्ष 2024-25 के वास्तविक राजस्व एवं व्यय का समायोजन, वर्ष 2025-26 के वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा तथा वर्ष 2026-27 के लिए वितरण कंपनियों की वार्षिक राजस्व आवश्यकता का विस्तृत आकलन किया गया है। आयोग ने बिजली खरीद व्यय, राज्य के भीतर पारेषण शुल्क, संचालन एवं अनुरक्षण व्यय, पूंजी निवेश, ऋण पर ब्याज, मूल्यह्रास, कार्यशील पूंजी पर ब्याज, बैंकिंग एवं वित्तीय प्रभार, गैर-शुल्क आय, सरकारी अनुदान तथा वितरण कंपनियों के राजस्व अंतर सहित विभिन्न वित्तीय पहलुओं पर विस्तार से निर्णय दिया है।आयोग ने अपने आदेश में बिजली दर निर्धारण से जुड़े विभिन्न विषयों को भी शामिल किया है। इनमें घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक तथा अन्य उपभोक्ता श्रेणियों की दरें, हरित ऊर्जा शुल्क, विद्युत चालित वाहनों के चार्जिंग केंद्रों की दरें, मुक्त अभिगम शुल्क, पारगमन शुल्क, क्रॉस-सब्सिडी अधिभार तथा अन्य नियामकीय प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।

सार्वजनिक सुनवाई के दौरान उपभोक्ताओं, उद्योग संगठनों तथा अन्य हितधारकों से प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर भी आयोग ने विचार किया। आदेश में बिजली खरीद लागत, वितरण हानियां, बहुमंजिला भवनों को विद्युत आपूर्ति, स्मार्ट मीटर, पूर्वभुगतान मीटर, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा, विद्युत आपूर्ति संहिता तथा सेवा गुणवत्ता से जुड़े विषयों पर आयोग के निर्णय दर्ज किए गए हैं।आयोग ने वितरण कंपनियों के लिए वर्ष 2026-27 के दौरान अनुपालन किए जाने वाले अनेक निर्देश भी जारी किए हैं। इनमें वितरण हानियों में कमी लाना, राजस्व संग्रह में सुधार, उपभोक्ता सेवाओं को बेहतर बनाना, स्मार्ट मीटरों का प्रभावी क्रियान्वयन, वित्तीय अनुशासन बनाए रखना तथा बिजली आपूर्ति व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और दक्ष बनाना शामिल है।

सीजेपी के आंदोलन के पीछे साजिश?

जिसको देखिए वह कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी पर संदेह कर रहा है। उससे जुड़े लोगों की पृष्ठभूमि खोजी जा रही है। किसी के बारे में कहा जा रहा है कि वह एक समय में नरेंद्र मोदी का प्रशंसक था किसी के बारे में जानकारी दी जा रही है और वह आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया हैंडल करता था। किसी को राहुल गांधी का विरोध करने वाला बताया जा रहा है तो किसी को ब्राह्मण विरोधी ठहराया जा रहा है। सोचें, युवाओं का एक समूह इस समय का सबसे ज्वलंत मुद्दा उठा कर सरकार के खिलाफ अभियान छेड़े हुए है। लेकिन जरूरी मुद्दे उठाने में असफल रहे लोग उनकी पृष्ठभूमि निकाल कर उनको निशाना बना रहे हैं। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके और तीनों प्रवक्ताओं सौरव दास, विजेता दहिया और आशुतोष रंका की पृष्ठभूमि खोज कर उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। कांग्रेस का इकोसिस्टम इन लोगों को युवाओं व छात्रों का एजेंडा हाईजैक करने के लिए भाजपा की ओर से प्लांट किया गया बता रहे है तो भाजपा के नेता सीजेपी की तुलना अन्ना हजारे व अरविंद केजरीवाल के आंदोलन से कर रहे हैं और इसे अर्बन नक्सल समूह कह रहे हैं।

सवाल है कि इस समूह और इसके आंदोलन को वर्तमान हालात से पैदा हुए असंतोष और युवाओं की बेचैनी की स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्यों नहीं माना जा सकता है? यह मानने में क्या समस्या है कि आज किशोर और युवा परीक्षा में हो रही गड़बड़ियों और नौकरी व रोजगार की घटती संभावनाओं की वजह से परेशान हैं और इसलिए उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिला तो वे वहां से अपनी परेशानी का इजहार कर रहे हैं? अभिजीत दीपके या सीजेपी से जुड़े दूसरे लोगों ने किशोरों और युवाओं को अपनी नाराजगी और असंतोष जाहिर करने का एक मंच दिया है, जहां से वर्तमान समय की सबसे ज्वलंत समस्या को उठा रहे हैं। सीजेपी के लोग पेपर लीक का विरोध कर रहे हैं, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की शुचिता बहाल करने की मांग कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। इन मांगों से भला विपक्ष की पार्टी या नेता को क्या समस्या हो सकती है? युवाओं का यह समूह भाजपा की विभाजनकारी राजनीति को भी निशाना बना रहा है। इसलिए आप इसे सांप्रदायिक भी नहीं कह सकते हैं।

तभी सवाल है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीजेपी के आंदोलन को विपक्ष, खास कर कांग्रेस पार्टी अपनी विफलता के तौर पर देख रही हो और इस वजह से इनको निशाना बनाया जा रहा हो? यह संभव है क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस इतने बड़े मुद्दे पर इस तरह का कोई आंदोलन नहीं खड़ा कर सकी इसलिए सीजेपी को मौका मिला। अगर कांग्रेस युवाओं के असंतोष को आवाज दे रही होती और उस असंतोष को प्रकट करने का मंच दे रही होती तो शायद सीजेपी जैसे किसी समूह की जरुरत नहीं पड़ती। ध्यान रहे सीजेपी अभी तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बना एक अकाउंट भर है। उसके पास न कोई संगठन है, न कोई बड़ा चेहरा है और न किसी राजनीतिक अभियान को चलाने का प्रशिक्षण या अनुभव है। फिर भी उस मंच से करोड़ों युवा जुड़े और उसके आह्वान पर हजारों लोग 40 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में सड़कों पर प्रदर्शन के लिए उतरे। कहने को कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने लगातार सोशल मीडिया में पोस्ट लिखी और प्रभावित छात्रों से मुलाकात की लेकिन यह समझने की जरुरत है कि समस्या जितनी बड़ी है उसके मुकाबले कांग्रेस का प्रयास बहुत छोटा और सुविधाजनक है। ड्राइंग रूम में बैठ कर 18 साल के छात्र से बात करना और उसकी वीडियो साझा करके सरकार पर हमला करना बहुत आसान है।

बहरहाल, जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए इक_ा हुए लोगों की संख्या असल में कितनी थी, किसके साथ ज्यादा भीड़ आई, किसका भाषण कैसा हुआ, कितनी देर प्रदर्शन चला, कौन जल्दी चला गया, किसको गर्मी लग रही थी और किसको एसी में बैठना था इन बातों का कोई मतलब नहीं है। जंतर मंतर पर यह तस्वीर दिखी कि हजारों लोग इक_ा हुए, जिनमें परीक्षा की गड़बड़ियों और पेपर लीक से परेशान छात्र थे तो नौकरी नहीं मिलने से परेशान युवा भी थे और रोजगार की घटती संभावना से बेचैन अधेड़ लोग भी थे। मुख्यधारा की मीडिया ने भले इसका बहिष्कार किया लेकिन राजधानी और आसपास के क्षेत्रों के तमाम छोटे बड़े यूट्यूबर वहां मौजूद थे। उन्होंने इसे अपने अपने हिसाब से कवर किया और देश के हर हिस्से में करोड़ों लोगों ने इसे देखा। किसी राजनीतिक या सामाजिक घटनाक्रम में लोगों में ऐसी उत्सुकता अरसे बाद देखने को मिली। किसान आंदोलन के बाद पहली बार ऐसे संगठित प्रतिरोध का स्वर पहली बार सुनाई दिया। अभी इसको इसी रूप में देखने की जरुरत है, जब तक कि कोई दूसरी बात प्रमाणित नहीं हो जाती है। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने इसे इसी रूप में देखा तो सीपीआई माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य और सीपीआई की एनी राजा ने भी इसे ऐसे ही देखा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

सरल, सादगी और संवेदनशीलता के साथ विकास यात्रा का सशक्त नेतृत्व

आदिवासी समाज से आने वाले मुख्यमंत्री साय अपनी संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों से गहराई से जुड़े हुए हैं।

तेजबहादुर सिंह भुवाल

किसान परिवार से निकलकर छत्तीसगढ़ प्रदेश के सर्वोच्च नेतृत्व तक पहुंचने वाले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने सरल व्यक्तित्व, विनम्र व्यवहार और जनसेवा की भावना से जनता के बीच एक अलग पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री साय का सार्वजनिक जीवन सादगी, जनसेवा और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुँचाने के संकल्प का प्रतीक माना जाता है। लंबे समय तक जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों, किसानों, वनवासियों, युवाओं, महिलाओं और वंचित वर्गों की समस्याओं को निकट से समझा और उनके समाधान के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। सत्ता के शीर्ष पद पर होने के बावजूद उनकी सादगी और सहजता आज भी उनकी सबसे बड़ी ताकत है।

मुख्यमंत्री साय आम जनता से सीधे संवाद को लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति मानते हैं। जनदर्शन, सुशासन तिहार और विभिन्न जनसंपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से वे स्वयं लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनके समाधान के लिए त्वरित पहल करते हैं। बुजुर्गों के प्रति सम्मान, बच्चों के प्रति स्नेह तथा जरूरतमंदों की सहायता के लिए तत्परता उनके व्यक्तित्व की विशेष पहचान है।

आदिवासी समाज से आने वाले मुख्यमंत्री साय अपनी संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों से गहराई से जुड़े हुए हैं। गांवों में बैठकर लोगों से चर्चा करना, उनकी समस्याओं को समझना और विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है।

पिछले ढाई वर्षों में छत्तीसगढ़ सरकार ने जनकल्याण, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, अधोसंरचना, निवेश और सुशासन के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। सरकार का लक्ष्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना रहा है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को 1000 रुपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इस वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 8,200 करोड़ रूपये का बजट महतारी वंदन योजना के लिए आवंटित किया है। महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ में महिलाओं के स्वावलंबन, स्वास्थ्य और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो लाखों महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार ला रही है।

छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसान हैं। राज्य सरकार ने धान खरीदी को प्राथमिकता देते हुए किसानों से 3100 रूपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी सुनिश्चित की तथा लाखों किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाया।

प्रदेश में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार ने बड़ी पहल करते हुए लाखों आवासों को स्वीकृति प्रदान की। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवासीय सुविधाओं का विस्तार हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तेज गति से चल रहे निर्माण कार्यों के चलते प्रदेश में लाखों जरूरतमंद परिवारों का पक्के घर का सपना साकार हो रहा है।

बस्तर के जंगलों में उत्पादित होने वाले तेंदूपत्ता, आदिवासी समाज की जिंदगी का अहम हिस्सा है। इसी तेंदूपत्ता के सहारे हजारों गांवों में गर्मियों के महीनों में रोज़गार मिलता है। इस काम में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल होती हैं, जिससे परिवार की कुल आय में संतुलन बनता है। यही वजह है कि तेंदूपत्ता संग्रहण को सरकार ग्रामीण रोजगार का मजबूत जरिया मानती है। राज्य सरकार ने तेन्दूपत्ता संग्राहकों को बड़ी रहत देते हुए तेंदूपत्ता संग्रहण दर में अहम बदलाव किया है। पूर्व में मिलने वाली राशि को 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये किया है। यह बढ़ोतरी सीधे-सीधे संग्राहकों लाभ पहुंचा रही है। जानकारों के अनुसार पहले बढ़ती महंगाई के मुकाबले संग्रहण की दर कम पड़ रही थी, लेकिन नई दर से मजदूरी और मेहनत का बेहतर मूल्य मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार सुरक्षा के साथ-साथ संवेदनशील पुनर्वास और विकास पर भी समान रूप से कार्य कर रही है। नक्सली सरेंडर, विक्टिम रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी-2025 के तहत आत्मसमर्पित नक्सलियों को वित्तीय सहायता, कौशल विकास प्रशिक्षण, रोजगार के अवसर तथा आवास जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराकर उन्हें सम्मानजनक और मुख्यधारा से जुड़ा जीवन प्रदान किया जा रहा है।

एक नवंबर 2024 से लागू छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति 2024-30 राज्य को निवेश और उद्योगों के लिए नई पहचान दे रही है। न्यूनतम शासन, अधिकतम प्रोत्साहन के सिद्धांत पर आधारित यह नीति उद्योग स्थापना की प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और निवेशक-अनुकूल बनाती है। व्यवसाय शुरू करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम 2.0, पूरी तरह ऑनलाइन आवेदन, समयबद्ध स्वीकृति और त्वरित प्रोसेसिंग जैसी आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। इससे उद्यमियों को कम समय में आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त हो रही हैं और कारोबार करने में सुगमता बढ़ी है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में मजबूत और आधुनिक परिवहन नेटवर्क के निर्माण पर विशेष जोर दिया गया है। राज्य में रेल, सड़क और हवाई संपर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है, जिससे उद्योग, व्यापार, पर्यटन और आम नागरिकों की आवाजाही पहले से अधिक सुगम हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों का निरंतर उन्नयन, नई सड़कों और पुलों का निर्माण तथा दूरस्थ क्षेत्रों को मुख्य मार्गों से जोड़ने के प्रयासों ने प्रदेश की कनेक्टिविटी को नई गति दी है। इससे माल परिवहन की लागत और समय में कमी आई है, जिससे उद्योगों और निवेशकों को सीधा लाभ मिल रहा है।

राज्य शासन की पहल से रेल नेटवर्क के विस्तार और नई रेल परियोजनाओं के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्रों, खनिज संपदा वाले इलाकों और प्रमुख शहरों को बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं, हवाई सेवाओं के विस्तार, नए एयर रूट और बेहतर विमानन सुविधाओं से राज्य की राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच और भी मजबूत हुई है। बेहतर परिवहन अवसंरचना के कारण छत्तीसगढ़ आज निवेश, व्यापार और पर्यटन के लिए अधिक आकर्षक बन रहा है। यह मजबूत कनेक्टिविटी राज्य के समग्र आर्थिक विकास को नई दिशा देने के साथ-साथ रोजगार और क्षेत्रीय विकास के नए अवसर भी सृजित कर रही है।

टिप्पणी

छवि से बंध जाना सही सोच नहीं

वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स का अपना महत्त्व है। इसलिए उन पर गौर किया जाना चाहिए। लेकिन कृत्रिम ढंग से उनमें दर्जा बढ़ाने की कोशिशें हानिकारक हैं। फिर रैंकिंग्स में उभरने वाली छवि से बंध जाना सही सोच नहीं है।

यह अच्छी खबर है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ी है। 500 विश्वविद्यालयों की इस ताजा सूची में भारत की 54 यूनिवर्सिटीज शामिल हुई हैं। इसमें भारत की नुमाइंदगी अब आईआईटी या आईआईएस जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों तक सीमित नहीं रह गई है। बल्कि कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, राज्यों के विश्वविद्यालय और केंद्रीय संस्थानों ने भी इसमें जगह बनाई है। हालांकि यह अप्रिय तथ्य अब भी कायम है कि टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में एक भी भारतीय विश्वविद्यालय नहीं है। टॉप 200 में भारत के सिर्फ तीन विश्वविद्यालय ही आए हैं। सबसे ऊपर 118वें स्थान पर आईआईटी दिल्ली आई है।

बहरहाल, शिक्षा संस्थानों के स्तर को जानने के लिए रैंकिंग्स भले एक प्रचलित माध्यम हों, लेकिन इनके आधार पर किसी देश में शिक्षा की वास्तविक स्थिति का अंदाजा लगाना सही नजरिया नहीं होगा। मसलन, क्यूएस रैंकिंग की यह एक बड़ी आलोचना है कि इसमें विश्वविद्यालय की अकादमिक प्रतिष्ठा को अत्यधिक महत्त्व दिया जाता है। इसका भार 40 प्रतिशत तक है। प्रतिष्ठा मनोगत पैमाना है, जो सर्वेक्षण में शामिल व्यक्तियों की जानकारी एवं पूर्व-धारणाओं से तय होती है। एक अन्य पैमाना विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों की उपस्थिति है। भारतीय विश्वविद्यालय इस पैमाने पर पिछड़ जाते हैं। इसलिए क्यूएस या ऐसी अन्य रैंकिंग्स में भारत की स्थिति अपने-आप में समस्या नहीं है। समस्या यूनिवर्सिटी शिक्षा तक सीमित वर्गों की पहुंच, वास्तविक अनुसंधान पर कम ध्यान, और जाने वाली शिक्षा का रोजगार बाजार से कमजोर संबंध हैं।

इस ओर ध्यान देने के बजाय रैंकिंग में आगे बढ़ने की होड़ का खराब असर यह हुआ है कि विश्वविद्यालयों में प्रति फैकल्टी प्रकाशनों की संख्या बढ़ाने और उन प्रकाशनों का आपस में उद्धरण देने जैसी विकृतियां उभरी हैं। इसलिए आवश्यकता रैंकिंग्स से आगे सोचने की है। इसके लिए उच्च शिक्षा के लिए जीडीपी का अधिक हिस्सा आवंटित करना, शिक्षक-छात्र अनुपात सुधारना और शोध संस्कृति को बढ़ावा देना अनिवार्य है। वैश्विक शोध नेटवर्क से जुड़ने और संकाय आदान-प्रदान को बढ़ावा देने की भी जरूरत है। रैंकिंग्स को पूरी तरह ठुकराना ठीक नहीं होगा, लेकिन इसमें उभरने वाली छवि से बंध जाना सही सोच नहीं है।

ब्लॉग

भारत और खाड़ी संकट का आर्थिक प्रभाव: सब कुछ स्थिर और सामान्य रहा

वी. अनंत नागेश्वरन

जब फरवरी के अंत में हवाई हमलों के कारण हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य बंद हो गया — ऐसा समुद्री मार्ग जिससे होकर दुनिया के कच्चे तेल का करीब एक-पांचवां हिस्सा और भारत के कच्चे तेल और खाना पकाने के गैस का अधिकांश हिस्सा गुजरता है — तो भारत के लिए कहानी पहले ही लिखी हुई लग रही थी। एक ऐसा देश, जो अपने कच्चे तेल का दस में से नौ हिस्सा और आधे से ज्यादा खाना पकाने के गैस का खाड़ी से आयात करता है, उसके लिए आम तौर पर यही उम्मीद की जा रही थी कि पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगेंगी, रसोई में गैस खत्म हो जाएगी, रुपये की कीमत गिरेगी और डॉलर के लिए होड़ मचेगी। लगभग चार महीने बाद, जब जलडमरूमध्य फिर से खुल गया और कच्चे तेल की आपूर्ति अपने संकट-पूर्व स्तर के करीब पहुँच गयी, तो इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। एक भी रिटेल आउटलेट बंद नहीं हुआ। जिस भी परिवार को सिलेंडर चाहिए था, उसे सिलेंडर मिल गया। भारत को न तो 1991 जैसे और न ही 2013 जैसे हालात का सामना करना पड़ा। व्यापक आर्थिक स्थिरता बनी रही।

यह कोई संयोग नहीं था और न ही यह सिफ़र् किस्मत की बात थी। यह एक ऐसे सरकार का काम था, जिसने वही तरीका अपनाया, जो उसने महामारी के समय अपनाया था — जानबूझकर और धीरे-धीरे कदम उठाना, एक ही बार में कोई बड़ा या नाटकीय बदलाव करने के बजाय एक उपाय के ऊपर दूसरे उपाय को जोड़ना। पहली प्राथमिकता घर-परिवार थे। इस पूरी अवधि के दौरान, एक भी रिटेल आउटलेट का स्टॉक खत्म नहीं हुआ और हर रसोईघर में सिलेंडर मौजूद रहा। आयात से जुड़ी लागत के कारण 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत 1,600 रुपये से ऊपर चली गई थी, फिर भी घरों के लिए इसकी कीमत 900 रुपये के आसपास ही रखी गई और सबसे गरीब लोगों के लिए तो यह कीमत और भी कम थी। महामारी के शुरुआती महीनों की यादें एक सबक थीं, जब प्रवासी मजदूरों में मची घबराहट के कारण गांवों की ओर लौटने वालों की लहर चल पड़ी थी। वाणिज्यिक और थोक उपयोगकर्ताओं को घरों की जरूरत को प्राथमिकता देने के लिए कहा गया।

पूरी अर्थव्यवस्था को चलाने वाले ईंधन के मामले में, सरकार ने इसका बोझ खुद उठाने का फ़ैसला किया, न कि इसे आम लोगों पर डाला। सरकार ने पेट्रोल और डीज़ल पर उत्पाद शुल्क में दस रुपये प्रति लीटर की कटौती की, जिससे उसे लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ, इसके अलावा विमानन ईंधन पर भी

बोझ कम किया गया। इसके बाद तेल विपणन कंपनियों ने दो महीने से ज़्यादा समय तक पंप पर कीमतें स्थिर रखीं और फिर एक बार मामूली बदलाव किया। इसके पीछे की वजह साफ़ है: ऐसी अनिश्चितता के समय में, सिफ़र् सरकार के पास ही जोखिम उठाने के लिए ज़रूरी बैलेंस शीट और समय होता है; और इसने परिवारों और कंपनियों पर असर डालने के बजाय राजकोषीय खाते पर बोझ डालने का विकल्प चुना। एयरलाइंस के लिए खास समर्थन तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए ऋण-गारंटी योजना, कोविड के दौर में अपनाए गए खास और असरदार उपायों के मॉडल पर ही आधारित थीं।

कीमत में राहत के पीछे आपूर्ति की मजबूत स्थिति थी। घरेलू रिफाइनरियों ने एक हफ्ते में ही रसोई गैस का उत्पादन आधा बढ़ा दिया, जिससे आयात से आने वाली गैस की कमी काफी हद तक पूरी हो गई। भारत ने जल्दी ही अपने स्रोतों का विस्तार किया, अमेरिका और रूस से खरीद बढ़ायी और नए आपूर्तिकर्ता देश जोड़े, ताकि जलडमरूमध्य से होकर कम ऊर्जा आये; साथ ही रूसी कच्चा तेल खरीदना जारी रखने के लिए ज़रूरी छूट भी हासिल कर ली। सरकार ने लंबी अवधि के लिए भी कदम उठाए: घरों को सिलेंडर के बदले पाइप से गैस पहुँचाना, कोयले गैसीकरण कार्यक्रम, ईथेनॉल मिश्रण को और बढ़ावा देना तथा प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात यात्रा के दौरान रणनीतिक तौर पर कच्चा तेल भंडारण पर सहमति। भारत उन कुछ देशों में से एक था, जिसने होर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुज़रने वाले जहाजों की संख्या बहुत कम हो जाने के बावजूद अपना कार्गो लाना जारी रखा।

बाहरी खातों को भी उतने ही धैर्य के साथ संभाला गया। सरकार ने सरकारी कज़र् की विदेशी संस्थागत खरीद पर लगी रोक और पूंजीगत लाभ टैक्स हटा दिए और पूर्ण पहुँच रूट के तहत प्रतिभूतियों का दायरा बढ़ाया, जिससे बॉन्ड मार्केट में पैसा आया। एक नई गैर-निवासी डॉलर जमा योजना से काफी बड़ी राशि में डॉलर आने की उम्मीद है। सालों में किए गए मुक्त व्यापार समझौते धीरे-धीरे अपने काम कर रहे थे: अप्रैल और मई 2026 के दौरान गैर-तेल, गैर-रत्न-आभूषण के अलावा वस्तु और सेवाओं का निर्यात पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 12 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया।

प्रमुख आंकड़े भरोसा दिलाते हैं। पिछले वित्त वर्ष में सकल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पैंतालीस अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो महामारी के बाद के वर्षों के सत्तर से अस्सी अरब डॉलर की सीमा को पार कर गया। चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 26 में जीडीपी का केवल 0.6 प्रतिशत था और अब उम्मीद है कि वित्त वर्ष 27 में यह इससे थोड़ा ही ज़्यादा होगा।

ईमानदारी से यह भी मानना होगा कि किस्मत ने भी साथ दिया। बंद होने के कुछ ही हफ्तों में कच्चा तेल एक सौ बीस डॉलर के पार पहुंच गया, लेकिन मई से चीन की तेल खरीद में कमी और अमेरिका के रिजर्व से लगातार तेल जारी होने से यह फिर से सौ डॉलर से नीचे आ गया, और चीन के उर्वरक निर्यात को फिर से शुरू करने से बजट को होने वाले भारी नुकसान से बचाया जा सका। अगर संघर्ष लंबे चले होते, या तेल एक सौ बीस डॉलर के करीब स्थिर रहता, तो स्थिति इतनी आरामदायक नहीं होती; ठोस नीति और अच्छी किस्मत दोनों ने अपना काम किया। वास्तव में, किस्मत अंततः ठोस नीतिकारों का ही साथ देती है।

आने वाले बदलावों के संकेत के तौर पर, गोल्डमैन सैक्स ने हाल ही में भारत के लिए अपने वृद्धि पूर्वानुमान को सीवाई 26 के लिए 6.8 प्रतिशत और वित्त वर्ष 27 के लिए 6.5 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है, जो पहले के पूर्वानुमानों से दोनों के लिए 30 बीपी अधिक हैं।

हालांकि, मध्यम अवधि में आत्मसंतोष की कोई गुंजाइश नहीं है। एक ऐसी दुनिया में जहाँ गठबंधन विभाजित हैं, हथियारबंद आपूर्ति श्रृंखलाएँ हैं और ऐसी पूंजी, जो कभी भी आ-जा सकती है, भुगतान संतुलन पर दबाव उस संघर्ष से भी लंबा रह सकता है, जिसने उसे खतरे में डाला था। भारत को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित करने पर बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए। संतुलित द्विपक्षीय निवेश संधि रूपरेखा, कर नीति में निश्चितता, राज्य सरकारों द्वारा अनुबंधों की अखंडता का सम्मान, भरोसेमंद लॉजिस्टिक्स और एकल-खिड़की मंजूरी, जो वास्तव में काम करती हो, अब उन वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को आकर्षित करेंगे, जो अपने जोखिम को कम करने के लिए अलग-अलग जगहों पर विस्तार करने की कोशिश कर रही हैं।

असली समस्या आयात पर निर्भरता है और यह सिफ़र् ऊर्जा से संबंधित नहीं है। माल व्यापार घाटा राष्ट्रीय आय का लगभग आठ प्रतिशत है; अगर तेल निकाल दें, तो यह पांच प्रतिशत है; तेल और सोना निकाल दें, तो भी यह साढ़े तीन प्रतिशत रहता है। तुलनात्मक रूप से बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। भारत को उन चीज़ों का उत्पादन देश में ही करना चाहिए जिन्हें वह प्रतिस्पर्धी ढंग से बना सकता है और जिनकी उसे ज़रूरत है। देश की कंपनियों और व्यापार संघों को अपने समझौतों पर ज्यादा मेहनत करना होगा — खासकर यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ के नए समझौते, जो इस साल लागू होंगे और श्रम-गहन निर्यात को बढ़ावा देंगे। यह सब कुशल लोगों के बिना संभव नहीं है, इसलिए युवाओं को व्यापार से जुड़े कौशल सिखाने का काम अब युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए।

इन कामों के लिए लगन और तेज़ी की ज़रूरत होगी। इन पर ध्यान देते हुए, सरकार को दक्षिण-पश्चिम मॉनसून पर भी ध्यान देना होगा जिसने अब तक निराश किया है, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आगमन पर भी विचार करना होगा कि भारतीय काम और भारतीय जीवन के लिए इसके मायने क्या होंगे। खाड़ी संघर्ष ने एक प्रकार की सहनशीलता की परीक्षा ली; आने वाले साल दूसरे प्रकार की परीक्षाएं लेंगे। भारत ने पहली परीक्षा को अच्छे ढंग से पूरा किया। यह आत्मविश्वास का एक कारण है — और अगले काम में लगने का भी कारण है।

(वी. अनंत नागेश्वरन भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)

मेरी पीएम मोदी से बात हो गई... राम मंदिर में चंदा चोरी पर बोले विनय कटियार, जेल जा सकते हैं चंपत राय

आर्यावर्त संवाददाता

अयोध्या। अयोध्या में चंदा चोरी मामले में तेजी से जांच चल रही है। जांच कर रही एसआईटी टीम ने मंदिर परिसर में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के साथ-साथ मंदिर के सहायक प्रशासक गोपाल राव से एक साथ पूछताछ की है। गबन मामले में चर्चा में आए गोपाल राव को लेकर विनय कटियार ने कहा कि वो सही आदमी नहीं हैं। साथ ही उन्होंने यह दावा करते हुए कहा कि इस मसले पर पीएम नरेंद्र मोदी से बात हो गई है। सब ठीक हो जाएगा।

फैजाबाद (अब अयोध्या) से सांसद रहे विनय कटियार ने गोपाल राव पर निशाना साधते हुए कहा, "वो सबसे बेकार आदमी हैं। पता नहीं किसने उसको यहां बनाकर भेजा था।" उन्होंने यह भी कहा कि हम कभी भी अयोध्या नहीं जाते थे, हम जब वहां पर गए तो गोपाल राव ने हमसे पूछा कि आप किसकी अनुमति से यहां आए हो।"

चंपत-गोपाल और अनिल जा सकते हैं जेल : कटियार

गोपाल राव को लेकर कटियार ने कहा, "हमने उनसे कहा कि तुम यहां नहीं रहने वाले हो तुम साउथ ही जाओ जहां से आए हो।" राम मंदिर को लेकर हुए आंदोलन पर कटियार ने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों ने राम मंदिर के लिए बलिदान दिया है। अब अविनाश पर डंडा चल जाए तो अच्छा है। यहां पर पैसे का जबरदस्त गबन हुआ है। विनय कटियार ने कहा, "यह साफ है कि पैसे का हेर-फेर हुआ है। मैंने इस मामले पर पीएम मोदी से बात की और उन्होंने पूछा कि आगे क्या होगा। मैंने उनसे कहा कि सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा को जेल जाना पड़े।" उन्होंने यह भी कहा कि किसी कारणवश चंपत राय अब तक जेल नहीं गए।

आरोपी अविनाश शुक्ला से भी पूछताछ जारी

दूसरी ओर, चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने कल गुरुवार को जेल में बंद एक आरोपी अविनाश शुक्ला को आगे की पूछताछ के लिए 24 घंटे की रिमांड पर लिया। पुलिस से जुड़े सूत्रों ने बताया कि मंदिर में चढ़ावे की रकम की गिनती का काम करने वाले अविनाश को कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उसे 24 घंटे की पुलिस रिमांड पर दे दिया। सूत्रों के अनुसार जांच के दौरान अविनाश के पास से 20 ।39 लाख रुपये बरामद किए गए थे।

SIT ने चंपत की अनिल और गोपाल से की पूछताछ

इससे पहले स्पेशल जांच दल (एसआईटी) ने कल गुरुवार को अयोध्या में राम मंदिर परिसर में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से एक साथ पूछताछ की थी। सूत्रों ने बताया कि एसआईटी ने पिछले 13 जून को गठित एसआईटी के सदस्य 6 दिन तक जांच करके प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपने के बाद कल दूसरी बार मंदिर परिसर में पहुंचे, तब जांच दल ने राय, मिश्रा और राव से अलग-अलग पूछताछ की थी।

पूछताछ के इतर, चंपत राय ने कहा कि अयोध्या में उनकी सेवा पूरी हो गई है लेकिन वह 'कलंक' के साथ अयोध्या से नहीं जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक एकांतवास में रह रहे चंपत राय ने अपने कुछ करीबी सहयोगियों से यह भी कहा कि उनके साथ 'धोखा' हुआ है। हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया कि वो किस पर निशाना साध रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के चंदा चोरी में कथित गबन का मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार ने पिछले महीने 13 जून को मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की थी। एसआईटी ने 23 जून को अपनी शुरुआती रिपोर्ट सौंप दी। इसके 2 दिन बाद 25 जून को मामले में पहली एफआईआर दर्ज की गई और मामले में नामजद 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया।

ट्रेलर की बैकिंग बनी काल, पिकअप चालक की मौत

सुलतानपुर। अयोध्या-प्रयागराज हाईवे पर देहात कोतवाली क्षेत्र के बिसानी मोड़ स्थित सूर्या ढाबा के पास गुरुवार देर रात एक सड़क हादसे में पिकअप चालक की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब हाईवे पर खड़े एक ट्रेलर ने बैक करते समय पिकअप वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान अमेठी जिले के पीपरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत खानापुर निवासी अमरनाथ मिश्रा उर्फ पप्पू (55) पुत्र स्वामीनाथ मिश्रा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह अपनी पिकअप लेकर घर लौट रहे थे। गांव के करीब बिसानी मोड़ स्थित सूर्या ढाबा के पास वाहन खड़ा कर सामान उतरवा रहे थे। इसी दौरान ट्रेलर ने अचानक बैक किया और पिकअप में टक्कर मार दी। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, उन्हें गंभीर हालात में जिला अस्पताल ले गए। जिला अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

सम्भव 6 .0 पोषण सुरक्षा विषय पर पोषण पाठशाला का आयोजन

आर्यावर्त संवाददाता

सुलतानपुर। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा जन-मानस एवं लाभार्थियों को विभाग की सेवाओं, पोषण प्रबन्धन, कुपोषण से बचाव के उपाय एवं स्वास्थ्य व पोषण शिक्षा आदि के सम्बन्ध में पूर्वान्हन 11:00 बजे से 01:30 बजे के मध्य प्रमुख सचिव महोदया एवं सचिव महिला कल्याण एवं निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की गरिमामयी उपस्थिति पोषण पाठशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य थीम ''गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक पोषण सुरक्षा रहा। इस पाठशाला में विभागीय अधिकारियों के अतिरिक्त विषय विशेषज्ञों द्वारा थीम की आवश्यकता, महत्व एवं उपयोगिता आदि के सम्बन्ध में न सिर्फ चर्चा की गई, बल्कि वीडियों कान्फ्रेन्सिग के माध्यम से लाभार्थियों एवं अन्य द्वारा पूंछे गये प्रश्नों का उत्तर भी दिया गया। पोषण पाठशाला का प्रसारण राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0) द्वारा वेबकास्ट के रूप में प्रसारित किया गया। इस कार्यक्रम का लाइव वेब-कास्ट भी किया गया जिसके माध्यम से लाभार्थी आम जन-मानस सीधे जुड़ सके। पोषण पाठशाला का लाइव वेब-कास्ट समस्त आंगनवाडी केन्द्रों पर किया गया, जिसमें गर्भवती, धात्री महिलाओं एवं अभिवावकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम में विशेषज्ञ/पैनालिस्ट के रूप में लीना जौहरी अपर मुख्य सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग, हर्षिता माथुर निदेशक आईसीडीएस, डा0 मिलिन्द वर्धन महा प्रबन्धक शिशु एवं बाल स्वास्थ्य एन0एच0एम0 रवी नारायण पाढी पोषण विशेषज्ञ यूनिसेफ,डा0 संदीप सेठ राज्य सलाहकार यूनीसेफ व मनीष उपाध्याय उप निदेशक पंचायतीराज विभाग सेराज इहमद उपनिदेशक आईसीडीएस उपस्थित रहे। उनके द्वारा बताया गया कि गर्भवती महिलाओं के नियमित जांच एवं टीकरण से एक स्वस्थ बच्चा प्राप्त होता है जिसमें कुपोषण होने की संभावना न के बराबर पायी जाती है इसलिए गर्भवती महिलायें एनेमिक न होने पाये जिससे बच्चा कुपोषण का शिकार न हो इसलिए सभी प्रसवपूर्व जांच एवं वजन कर लिया जाय जन्म के समय कम वजन वाले नवजात शिशु का विशेष प्रबन्धन किया जाय 0-6 माह में 7 बार गृह भ्रमण कर पोषणप्रबन्धन पर बल दिया जाय एवं सैम प्रबन्धन समय पर पहचान एवं उपचार कराया जाय। के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की गयी। इस कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी शरद कुमार त्रिपाठी, बाल विकास परियोजना अधिकारी दयाराम, फूल कुमार, राजेन्द्र प्रसाद, राहुल त्रिपाठी, प्रवीण कुमार, ममता नायक मुख्य सेविका मीना सिंह,नेहा यादव, सविता गुप्ता उमेश तिवारी, जिला समन्वयक पोषण अभियान उपस्थित रहे।

'मिस्त्री मान जाओ' से फेमस हुई निशा चौहान की पति ने कर दी हत्या, खुद को भी घोंपा चाकू, सीसीटीवी में कैद वारदात

आर्यावर्त संवाददाता

मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से एक बेहद सनसनीखेज और रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां सरूरपुर थाना क्षेत्र के हर्रा कस्बे में शुक्रवार की सुबह एक घरेलू विवाद ने खूनी रूप अख्तियार कर लिया। सोशल मीडिया पर अपनी रील्स और वीडियो के लिए मशहूर इन्फ्लुएंसर निशा चौहान की उनके ही पति प्रदीप ने चाकुओं से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी। दिल दहला देने वाली बात यह है कि पत्नी की जान लेने के बाद आरोपी पति ने खुद पर भी चाकू से ताबड़तोड़ कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। यह पूरी खूनी वारदात घर में लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस से मिली शुरुआती जानकारी के अनुसार, निशा चौहान सरूरपुर थाने के अंतर्गत आने वाले कस्बा हर्रा में रहती थीं। वह

सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थीं और अपने इलाके में एक ब्यूटी पार्लर का संचालन भी करती थीं। हाल ही में उनका एक वीडियो जिसका टाइटल 'मिस्त्री मान जाओ' था, सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ था। शुक्रवार की सुबह किसी बात को लेकर निशा और उनके पति प्रदीप के बीच अनबन शुरू हुई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि प्रदीप ने गुस्से में आकर आपा खो दिया और निशा पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। निशा की चीख-पुकार सुनकर जब तक परिवार और आसपास के लोग मौके पर जुटते, तब तक अत्यधिक खून बह जाने के कारण निशा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था।

पत्नी को मारने के बाद पति ने खुद को भी गोदा, हालत गंभीर

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति प्रदीप ने खौफनाक कदम उठाया। उसने उसी चाकू से अपने शरीर पर भी कई गहरे वार किए। लहूलुहान हालत में चीख-पुकार मचने पर स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल पति प्रदीप को आनन-फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। पुलिस का कहना है कि प्रदीप के होश में आने और उसका बयान दर्ज होने के बाद ही इस जघन्य हत्याकांड की असली वजह सामने आ पाएगी।

मासूम बच्चों पर टूटा दुखों का पहाड़, सदमे में तीन बच्चे

इस खौफनाक वारदात ने हंसते-खेलते परिवार को पूरी तरह तबाह कर दिया है। निशा और प्रदीप के तीन बच्चे हैं, जो इस घटना के बाद से गहरे सदमे में हैं। सबसे बड़ा बेटा देव (16 वर्ष) है। दूसरा बेटा एलिक्स (14 वर्ष) है। सबसे छोटी एक 11 वर्ष की बेटी है। आंखों के सामने मां की मौत और पिता को अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी-मौत से जूझते देख तीनों बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है।

फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य, CCTV फुटेज पुलिस के कब्जे में

घटना की गंभीरता को देखते हुए सरूरपुर थाना पुलिस के साथ-साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम भी मौके पर पहुंच गई। टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और खून के नमूने व अन्य भौतिक साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस ने घर में लगे CCTV कैमरों की फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है, जिसमें यह पूरी वारदात रिकॉर्ड हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला पति-पत्नी के बीच आपसी विवाद का ही प्रतीत हो रहा है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

आधुनिक युग में भी हल-बैल से खेती कर परिवार का पेट पाल रहे किसान नकछेद

आर्यावर्त संवाददाता

बल्दीराय/सुल्तानपुर। एक ओर जहां आधुनिक कृषि में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और नई तकनीकों का बोलबाला है, वहीं बल्दीराय क्षेत्र के ग्राम पूरे दुआ शाह के किसान नकछेद आज भी हल-बैल के सहारे खेतों की जुताई कर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं। क्षेत्र में यह दृश्य लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है।

किसान नकछेद का कहना है कि आर्थिक तंगी, छोटे जोत का आकार और आधुनिक कृषि यंत्रों का बढ़ता खर्च उन्हें आज भी पारंपरिक खेती करने के लिए मजबूर करता है। उनका मानना है कि हल-बैल से खेती करने में भले अधिक मेहनत लगती हो, लेकिन इससे मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहती है और डीजल

पर निर्भरता नहीं रहती। देश के कई हिस्सों में आज भी कुछ छोटे और सीमांत किसान हल-बैल से खेती करते हैं, हालांकि अधिकांश क्षेत्रों में ट्रैक्टरों का उपयोग तेजी से बढ़ चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि आधुनिकता के इस दौर में भी नकछेद जैसे किसान कृषि की पुरानी परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। उनका संघर्ष यह बताता है कि गांवों में आज भी कई परिवार सीमित संसाधनों के बीच खेती कर अपनी आजीविका चला रहे हैं।

जिले की इन चोरियों का हुआ अनावरण

सुल्तानपुर। एसपी द्वारा किए गए खुलासे के अनुसार जयसिंहपुर थाना क्षेत्र नगईपुर गांव में 13 मार्च को प्रमोद पांडेय के घर में,16 मार्च को शमशेर बहादुर सिंह के घर में हुई चोरी, मोतिगरपुर थाना क्षेत्र पारस पट्टी गांव में संदीप यादव के घर 24 अप्रैल को हुई चोरी, कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के नकराही लोलेपुर गांव में सुरेश कुमार दुबे के यहां 17 जून को हुई चोरी व 19 जून को अनुराग वर्मा निवासी मनिका पुर परासिन के घर हुई चोरी, चांदा थाना क्षेत्र दरबारपुर निवासी प्रतिमा तिवारी के घर हुई चोरी, कूरेभार थाना क्षेत्र के बरौला गांव निवासी बाबूराम यादव के घर 20 मई को हुई चोरी व गोसाईगंज थाना क्षेत्र के इनायतपुर गांव में तोईयब के घर 21 जून को हुई चोरी शामिल है। साथ ही प्रयागराज जिले की तीन, अम्बेडकर नगर की एक, अयोध्या जिले की 03 चोरियों का भी खुलासा सुल्तानपुर पुलिस द्वारा किया गया है।

वाराणसी दालमंडी चौड़ीकरण के तहत वीडीए का ध्वस्तीकरण अभियान तेज, सात भवनों को किया जाना है ध्वस्त

आर्यावर्त संवाददाता

वाराणसी। दालमंडी चौड़ीकरण परियोजना के अंतर्गत अतिक्रमण हटाने का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) द्वारा शुक्रवार को दोपहर में ध्वस्तीकरण अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत दालमंडी क्षेत्र में सात चिन्हित भवनों को ध्वस्त किया जा रहा है। वीडीए ने पहले ही संबंधित भवन स्वामियों को नोटिस जारी कर मकान खाली करने के निर्देश दिए थे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान नियमानुसार चलेगा और केवल चिन्हित भवनों को ही हटाया जाएगा।

विभागीय सूत्रों के अनुसार, ध्वस्तीकरण अभियान निर्धारित समय से काफी पीछे चल रहा था, लेकिन अब इसे इस माह के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। लगातार कार्रवाई के चलते यह सुनिश्चित

किया जा रहा है कि सभी प्रक्रियाएं समय पर पूरी हों।

वीडीए के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य दालमंडी क्षेत्र में यातायात की समस्या को हल करना और चौड़ीकरण कार्य को सुगम बनाना है। इसके तहत अतिक्रमण के कारण बाधित हो रहे विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है।

ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान वीडीए ने सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने का आश्वासन दिया है। अधिकारियों का कहना है कि इस प्रकार के अभियान से न केवल क्षेत्र का विकास होगा, बल्कि स्थानीय निवासियों को भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इस अभियान के सफल कार्यान्वयन के लिए वीडीए ने सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया है। इसके अलावा, स्थानीय निवासियों को भी इस प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वीडीए का कहना है कि यह कदम आवश्यक है ताकि क्षेत्र में यातायात की समस्या को हल किया जा सके और विकास कार्यों को गति दी जा सके।

जिले के आठ चोरियों सहित गैर जनपद की 15 चोरियों का एसपी ने किया खुलासा

सुलतानपुर। जिले के अलग थाना क्षेत्रों में पिछले 03 महीनों में हुई 08 बड़ी चोरियों का एसपी चारु निगम ने पुलिस लाइन सभागार में खुलासा किया। खुलासा करते हुए एसपी ने बताया कि सीतापुर जिले के चोरों का शातिर गिरोह प्रदेश के अलग अलग जिलों में चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाता था। जिले में हुई चोरियों के खुलासे के लिए कई टीमों का गठन किया गया तो जानकारी में आया कि गैर जनपद के चोरों द्वारा जिले में आकर चोरी की घटना को अंजाम देकर चार पहिया वाहन से फरार हो जाते थे। जवाबी फायरिंग में अनिकेत चौहान, आकाश, मिथिलेश गोली लगने से घायल हो गए। घायलों को पुलिस लेकर जयसिंहपुर सीएचसी पहुंची, जहां सभी का इलाज कराया गया। उन्होंने बताया गिरफ्तार आरोपियों से साढ़े 11 लाख रूपये नगद, 107 ग्राम सोना कीमत 15 लाख 10 हजार, 01 किलो चांदी कीमत 02 लाख 40 हजार सहित 03 तमंचा व जिंदा कारतूस बरामद किया।

नोएडा एयरपोर्ट के पास आम लोगों को मिलेगा सपनों का घर, यमुना अथॉरिटी ला रही है नई प्लॉट योजना

आर्यावर्त संवाददाता

नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के आसपास घर बनाने की चाहत रखने वाले कम आय वर्ग के लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) क्षेत्र में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्ग के परिवारों को ध्यान में रखते हुए एक विशेष किफायती आवासीय प्लॉट योजना लाने की तैयारी की जा रही है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को जेवर एयरपोर्ट और प्रस्तावित फिल्म सिटी जैसी बड़ी परियोजनाओं के नजदीक जमीन मुहैया कराना है, जो महंगे और बड़े प्लॉट खरीदने में सक्षम नहीं हैं। प्राधिकरण की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत मुख्य रूप से बेहद छोटे आकार के प्लॉट आवंटित किए

जाएंगे, ताकि इनकी कुल कीमत आम आदमी और श्रमिकों के बजट के दायरे में रहे।

40 वर्ग मीटर के प्लॉट होंगे शामिल

इस नई योजना के तहत प्राधिकरण ने मुख्य रूप से 40 वर्ग मीटर के छोटे आवासीय भूखंडों को शामिल किया है। इन प्लॉटों की कुल कीमत बेहद कम होने की उम्मीद है, जिससे गरीब परिवारों का दिल्ली-एनसीआर के इस सबसे तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्र में अपना आशियाना होने का सपना साकार हो सकेगा।

कौन होगा पात्र?

पात्रता की बात करें तो यह योजना विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और कम आय वर्ग (LIG) के परिवारों के लिए तैयार की गई है। इस प्लॉट योजना में वही आवेदन कर सकेंगे, जिन्होंने यमुना प्राधिकरण के स्थापित नियमों के मुताबिक पहले किसी अन्य योजना में भूखंड का लाभ नहीं लिया हो। इन सभी प्लॉटों का आवंटन पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से लकी ड्रॉ प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।

दो हजार प्लॉट लाने की तैयारी में प्राधिकरण

यमुना प्राधिकरण के एसीईओ शैलेंद्र कुमार भाटिया ने बताया कि गरीब, कमजोर वर्ग और श्रमिकों के लिए यमुना प्राधिकरण द्वारा जेवर एयरपोर्ट के पास 40 वर्ग मीटर के 2,000 प्लॉट लाने की तैयारियां की जा रही हैं। इस संबंध में यमुना प्राधिकरण में एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह योजना जल्द ही लाई जाएगी, जिससे कमजोर वर्ग के लोगों को एयरपोर्ट के पास अपने सपनों का घर बनाने का अवसर मिल सकेगा।

कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी का जोरदार हुआ स्वागत

व्यक्तिगत अहंकार और गुटबाज़ी की राजनीति के लिए कांग्रेस में कोई स्थान नहीं: राजेंद्र पाल गौतम

आर्यावर्त संवाददाता

सुलतानपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी, पूर्व मंत्री, दिल्ली के विधायक राजेंद्र पाल गौतम के शुक्रवार को सुल्तानपुर आगमन पर जिला/शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से अमहट चौराहे पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह देखने को मिला, पूरे जोश व अनुशासन के साथ माला पहनाकर और गुलाब का फूल देकर कांग्रेसियों ने उनका अभिनंदन किया। स्वागत कार्यक्रम का नेतृत्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा एवं शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने किया। उनके नेतृत्व में पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने राजेंद्र पाल गौतम का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी बनाए जाने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। नवनियुक्त प्रदेश

कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य जनता के बीच रहकर उनके मुद्दों को मजबूती से उठाना है, संगठन को बूथ स्तर तक सशक्त बनाते हुए हर कार्यकर्ता को सक्रिय और जिम्मेदार बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करना होगा, मैं सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि आपसी मतभेद, गुटबाज़ी और एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाज़ी से संगठन को नुकसान पहुंचता है,अब व्यक्तिगत अहंकार और खेमेबाज़ी की राजनीति के लिए कांग्रेस में कोई स्थान नहीं होगा। सभी लोग आपसी संवाद, अनुशासन और संगठन की भावना के साथ काम करें, जनता की लड़ाई ही हमारी प्राथमिकता है, कांग्रेस संविधान, सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक मूल्यों और आमजन के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी ताकत के साथ संघर्ष करती रहेगी। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने कहा कि राजेंद्र पाल गौतम के संगठनात्मक अनुभव, संघर्षशील व्यक्तित्व और जनसरोकारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का लाभ उत्तर प्रदेश कांग्रेस को मिलेगा। उनके नेतृत्व में संगठन को नई ऊर्जा और मजबूती प्राप्त होगी तथा कांग्रेस कार्यकर्ता पूरी निष्ठा,अनुशासन और समर्पण के साथ जनहित के मुद्दों को लेकर जनता के बीच संघर्ष करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा संविधान, सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक मूल्यों और आमजन के अधिकारों की लड़ाई लड़ती रही है। प्रदेश प्रभारी के मार्गदर्शन में संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक सशक्त बनाने का कार्य किया जाएगा। जानकारी के अनुसार, राजेंद्र पाल गौतम लखनऊ से सड़क मार्ग द्वारा वाराणसी जा रहे थे उनके साथ पूर्व एमएलसी वरिष्ठ कांग्रेस नेता दीपक सिंह, बाराबंकी सांसद तनुज पुनिया व अन्य कई प्रदेश के नेता भी थे। इस दौरान सुल्तानपुर के अमहट चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका पूरे जोशखरोश के साथ स्वागत किया।

क्या हफ्ते में 150 मिनट की एक्सरसाइज से दिल और दिमाग दोनों रह सकते हैं फिट?

दिल और दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए नियमित एक्सरसाइज बेहद जरूरी है। शारीरिक एक्टिविटी की कमी से कई स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हफ्ते में सिर्फ 150 मिनट की एक्सरसाइज दिल और दिमाग दोनों को फिट रखने के लिए काफी है। आइए जानते हैं।

आजकल भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल, लंबे समय तक बैठे रहकर काम करना और शारीरिक एक्टिविटी की कमी कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन रही है। ऐसे में नियमित एक्सरसाइज को स्वस्थ लाइफस्टाइल का अहम हिस्सा माना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि रोजमर्रा की दिनचर्या में थोड़ी-सी शारीरिक एक्टिविटी भी शरीर को एक्टिव रखने में मदद कर सकती है। हालांकि यह सवाल अक्सर लोगों के मन में रहता है कि अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए आखिर कितनी देर एक्सरसाइज करना जरूरी है।

इसी को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञ और कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं नियमित शारीरिक एक्सरसाइज के लिए कुछ मानक सुझाव देती हैं। इन्हीं में से एक है 150 मिनट तक मध्यम तेजी वाली शारीरिक एक्टिविटी करने की सलाह। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि पूरे 150 मिनट एक ही दिन या एक साथ व्यायाम करना जरूरी है। इसे पूरे हफ्ते में अपनी सुविधा के अनुसार बांटा जा सकता है। आइए जानते हैं कि 150 मिनट की एक्सरसाइज से दिल और दिमाग पर क्या असर पड़ सकता है, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी शामिल की जा सकती हैं और एक्सरसाइज करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

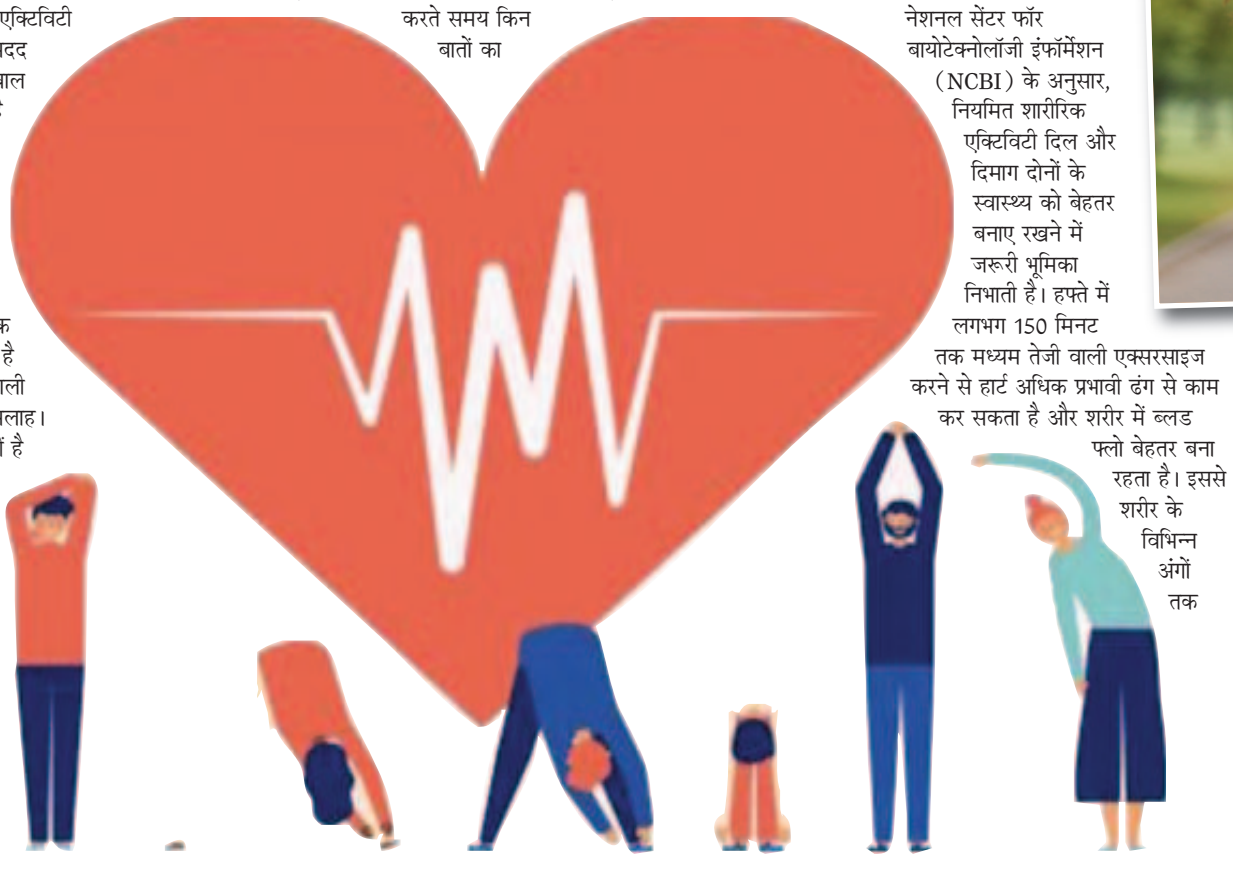

150 मिनट की एक्सरसाइज से दिल और दिमाग को कैसे मिलते हैं फायदे?

नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन (NCBI) के अनुसार, नियमित शारीरिक एक्टिविटी दिल और दिमाग दोनों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में जरूरी भूमिका निभाती है। हफ्ते में लगभग 150 मिनट तक मध्यम तेजी वाली एक्सरसाइज करने से हार्ट अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकता है और शरीर में ब्लड फ्लो बेहतर बना रहता है। इससे शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचने में मदद मिलती है।

नियमित एक्सरसाइज मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी मानी जाती है। यह तनाव कम करने, मूड बेहतर रखने और दिमाग की कामकाज को बनाए रखने में सहायक हो सकता है। इसके अलावा एक्टिव लाइफस्टाइल लंबे समय तक शारीरिक क्षमता बनाए रखने में भी मदद करती है। हालांकि हर व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य स्थिति और शारीरिक क्षमता अलग होती है, इसलिए व्यायाम की शुरुआत अपनी क्षमता के अनुसार करनी चाहिए। अगर पहले से कोई गंभीर बीमारी है, तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर रहता है।

हफ्ते में 150 मिनट की एक्सरसाइज में कौन-कौन सी गतिविधियां शामिल की जा सकती हैं?

150 मिनट की मध्यम तेजी वाली शारीरिक एक्टिविटी को पूरे हफ्ते में अलग-अलग दिनों में बांटा जा सकता है। इसमें तेज चाल से चलना, साइकिल चलाना, तैराकी, हल्की जॉगिंग, डांस करना, सीढ़ियां चढ़ना, बागवानी या घर के कुछ एक्टिव काम भी शामिल किए जा सकते हैं।

आमतौर पर इसे सप्ताह में पांच दिन, रोज करीब 30 मिनट करके पूरा किया जा सकता है। अपनी पसंद और सुविधा के अनुसार अलग-अलग एक्टिविटी को भी इसमें शामिल किया जा सकता है।

एक्सरसाइज करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हल्का वार्म-अप करें और अंत में शरीर को आराम देने के लिए कूल-डाउन भी करें। शुरुआत धीरे-धीरे करें और अपनी क्षमता के अनुसार समय व तेजी बढ़ाएं।

एक्सरसाइज के दौरान पर्याप्त पानी पिएं और आरामदायक कपड़े व जूते पहनें। अगर व्यायाम करते समय सीने में दर्द, चक्कर, सांस लेने में परेशानी या असामान्य थकान महसूस हो, तो तुरंत रुकें और डॉक्टर से संपर्क करें। पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोग डॉक्टर की सलाह के बाद ही नया व्यायाम शुरू करें।

क्या आप सुबह अलार्म बजने से पहले उठ जाते हैं?

प्राकृतिक

कई लोग सुबह अलार्म बजने से पहले उठ जाते हैं, जबकि कुछ लोग अलार्म बजने के बाद भी उठने के लिए जूझते रहते हैं। अगर आप सुबह जल्दी उठने वालों में से एक हैं तो इसका कारण आपका शरीर और मन हो सकता है। यह एक अच्छी आदत है और इससे आपका दिन बेहतर ढंग से शुरू हो सकता है। आइए जानते हैं कि सुबह अलार्म से पहले उठने के पीछे का कारण क्या है।

शरीर की आंतरिक घड़ी

आपके शरीर की अपनी एक आंतरिक घड़ी होती है, जिसे जैविक घड़ी कहा जाता है। यह घड़ी आपको बताती है कि कब सोना है और कब उठना है। अगर आप हर दिन एक ही समय पर सोते और उठते हैं तो आपका शरीर इस समय को पहचान लेता है और खुद-ब-खुद उसी समय पर जागने की आदत डाल लेता है। इससे आप बिना अलार्म के भी आसानी से उठ जाते हैं।

सोने की आदत बनाना

अगर आप नियमित रूप से एक ही समय पर सोते हैं तो आपकी नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है। इससे नींद गहरी होती है और आप सुबह तरोताजा महसूस करते हैं। इसके अलावा एक निश्चित समय पर सोने से आपका शरीर आराम महसूस करता है और सुबह उठने में कोई दिक्कत नहीं होती। यह आदत आपके शरीर को जैविक घड़ी के अनुसार काम करने में मदद करती है, जिससे आप बिना अलार्म के भी जल्दी उठ जाते हैं।

रोशनी का महत्व

सुबह की पहली किरण आपके शरीर को बताती है कि दिन शुरू हो गया है। अगर आप अपने कमरे में सुबह की रोशनी आने दें तो आपका शरीर खुद-ब-खुद जाग जाएगा। इसके लिए आप पर्दे हटाकर खिड़की खोल सकते हैं या फिर प्राकृतिक रोशनी आने वाली जगह पर सोने की कोशिश कर सकते हैं। इससे आपका शरीर जैविक घड़ी के अनुसार काम करेगा और आप बिना अलार्म के भी जल्दी उठ जाएंगे।

मानसिक तैयारी

अगर आप रात को सोने से पहले यह सोच लें कि सुबह उठकर क्या करना है तो आपका मन पहले से ही तैयार हो जाता है। इससे आप सुबह उठते ही अपने कामों में लग जाते हैं और आलस्य नहीं आता। इसके अलावा आप अपने दिमाग को शांत रखने के लिए ध्यान या सांस लेने के अभ्यास भी कर सकते हैं, जिससे आप तरोताजा महसूस करेंगे और उठते ही सक्रिय हो जाएंगे।

स्वस्थ जीवनशैली

स्वस्थ जीवनशैली अपनाने से भी सुबह जल्दी उठने में मदद मिलती है। इसके लिए आपको संतुलित भोजन, नियमित कसरत और पर्याप्त पानी पीना चाहिए। इसके अलावा तनाव मुक्त रहने के लिए योग या ध्यान कर सकते हैं। इन सभी तरीकों से आप आसानी से अपनी सुबह की दिनचर्या को बेहतर बना सकते हैं और बिना अलार्म के भी जल्दी उठ सकते हैं। रात को जल्दी सोने से भी सुबह जल्दी उठना आसान हो जाता है।

फर्श की टाइल्स का रंग हो गया है पीला? इन 5 तरीकों से दोबारा करें सफेद

नींबू

फर्श की टाइल्स को साफ रखना एक मुश्किल काम हो सकता है, खासकर जब उनका रंग पीला पड़ने लगे। यह समस्या आमतौर पर गंदगी, तेल और अन्य गंदे पदार्थों के कारण होती है, जो टाइल्स के ऊपर जमा हो जाते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार तरीके बताएंगे, जिनकी मदद से आप बिना ज्यादा मेहनत के अपने फर्श की टाइल्स को फिर से चमकदार और सफेद बना सकते हैं।

बेकिंग सोडा और पानी का करें इस्तेमाल

फर्श की टाइल्स को साफ करने के लिए आप बेकिंग सोडा और पानी का घोल बना सकते हैं। इसके लिए एक कप बेकिंग सोडा में थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें। इस पेस्ट को टाइल्स पर लगाकर कुछ मिनट छोड़ दें, फिर इसे ब्रश से रगड़ें। इससे गंदगी और दाग हट जाएंगे और टाइल्स फिर से चमकदार हो जाएंगी। यह तरीका न केवल असरदार है, बल्कि सुरक्षित भी है, क्योंकि इसमें कोई हानिकारक केमिकल नहीं होता है।

सिरका और पानी का बनाएं मिश्रण

सिरका और पानी का घोल भी फर्श की टाइल्स को साफ करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। इसके लिए एक बाल्टी पानी में 2-3 कप सफेद सिरका मिलाएं और इस मिश्रण को स्पंज या झाड़ू की मदद से पूरे फर्श पर फैलाएं। कुछ देर के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें, फिर साफ पानी से धो लें। इससे न केवल टाइल्स की गंदगी हटेगी, बल्कि उनका रंग भी फिर से चमकदार हो जाएगा।

के रस का करें उपयोग

नींबू का रस प्राकृतिक रूप से सतह को सफेद करने वाला होता है, जिसे आप टाइल्स पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए एक नींबू काटकर उसका रस सीधे दाग वाले हिस्से पर निचोड़ें और कुछ देर के लिए छोड़ दें, फिर ब्रश से रगड़ें। इससे दाग आसानी से हट जाएंगे और टाइल्स का रंग भी फिर से चमकदार हो जाएगा। यह तरीका न केवल असरदार है, बल्कि सुरक्षित भी है, क्योंकि इसमें कोई हानिकारक केमिकल नहीं होता है।

हाइड्रोजन पेरॉक्साइड आएगा काम

हाइड्रोजन पेरॉक्साइड एक शक्तिशाली क्लीनर होता है, जिसे आप फर्श की टाइल्स पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए एक कप हाइड्रोजन पेरॉक्साइड को 2 कप पानी में मिलाकर स्प्रे बोतल में भर लें और इसे दाग वाले हिस्से पर स्प्रे करें, फिर ब्रश से रगड़ें। इससे दाग आसानी से हट जाएंगे और टाइल्स का रंग भी फिर से चमकदार हो जाएगा। इसे इस्तेमाल करने के बाद एक बार पानी से दोबारा टाइल्स साफ कर लें।

सॉफ्ट ब्रश या स्पंज होगा उपयोगी

फर्श की टाइल्स को साफ करने के लिए सॉफ्ट ब्रश या स्पंज का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है, ताकि उन पर खरोंच न आएं। कठोर ब्रश या झाड़ू का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि इससे टाइल्स पर खरोंच पड़ सकती हैं और उनका रंग भी फीका पड़ सकता है। इन सरल तरीकों को अपनाकर आप फर्श की टाइल्स को आसानी से साफ कर सकते हैं और उनका रंग फिर से चमकदार बना सकते हैं।

छोटे गैस सिलेंडर्स का क्रेज खत्म? 80% गिरी अप्पू-छोटू-मुन्ना की डिमांड

देश के डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना है कि बच्चों के नाम पर क्रिएटिव तरीके से नाम रखे गए इन पोर्टेबल गैस सिलेंडरों की मांग में 80 फीसदी से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। इसका प्रमुख कारण वेस्ट एशिया में युद्ध के बाद इनकी कीमतें दोगुनी होना है। 5 किलो वाले इन सिलेंडरों का इस्तेमाल मुख्य रूप से प्रवासी मज़दूर और छात्र करते हैं, और इन्हें पहचान के सबूत के तौर पर सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर सीधे खरीदा जा सकता है।

ईरान वॉर के दौरान ना सिर्फ कच्चे तेल बल्कि गैस की कीमतों में भी काफी इजाफा देखने को मिला है। एलपीजी की सप्लाई काफी होने के कारण इस दौरान गैस सिलेंडर की कीमतों में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। यहां तक कि अप्पू-छोटू-मुन्ना जैसे नामों से मशहूर हुए 5 किलो वाले गैस सिलेंडर के दाम भी आसमान पा पहुंच गए। जिसकी वजह से इनकी डिमांड में काफी गिरावट देखने को मिली है। लाइव मिंट की रिपोर्ट में कम से कम चार डिस्ट्रीब्यूटर्स के हवाले से कहा गया है कि बच्चों के नाम पर रखे गए इन पोर्टेबल गैस सिलेंडरों की मांग वेस्ट एशिया वॉर के बाद कीमतें दोगुनी होने पर गिर गई।

5 किलोग्राम के इन सिलेंडरों का इस्तेमाल मुख्य रूप से प्रवासी मजदूर और छात्र करते हैं, और इन्हें सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर आसानी से खरीदा जा सकता है। मांग में आई इस भारी गिरावट से शहरों में मजदूरों की वापसी पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कुकिंग गैस की कमी के दौरान वे शहर छोड़कर चले गए थे। मांग में गिरावट और कीमतों में बढ़ोतरी एक ही समय पर हुई। दिल्ली में, इन छोटे सिलेंडरों—जिन्हें तकनीकी रूप से फ्री ट्रेड LPG (FTL) सिलेंडर कहा जाता है—की कीमत मार्च में 323 रुपए से बढ़कर जून में 821.50 रुपए हो गई। FTL सिलेंडर ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ 'छोटू' और 'मुन्ना' (इंडियनऑयल), 'भारतगैस मिनी' (BPCL) और 'HP गैस अप्पू' (HPCL) जैसे ब्रांड नामों से बेचती हैं।

80 से 90 फीसदी तक कम हुई डिमांड

दिल्ली के LPG डिस्ट्रीब्यूटर ने मीडिया रिपोर्ट में कहा कि संकट शुरू होने के तुरंत बाद FTL की मांग बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब लोग अपने सिलेंडर रिफिल कराने के लिए वापस नहीं आ रहे हैं, खासकर मई के बाद से। पूरे देश में FTL सिलेंडरों की मांग में लगभग 80 फीसदी की गिरावट आई है, और कुछ मामलों में तो यह 90 फीसदी तक है।

FTL सिलेंडर एक पोर्टेबल कुकिंग गैस कैनिस्टर है जिसे खरीदने के लिए सिर्फ आधार वेरिफिकेशन की जरूरत होती है। यह 2kg और 5kg के सुविधाजनक साइज में आता है, जो इसे छात्रों, प्रवासी मज़दूरों और बार-बार जगह बदलने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा बनाता है। इसे कमर्शियल LPG की कैटेगिरी में रखा गया है और इस पर कोई सब्सिडी नहीं मिलती है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने वॉर के दौरान 5kg के सिलेंडरों की उपलब्धता बढ़ाई थी।

बुधवार को, सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने कमर्शियल सिलेंडरों की कीमतें कम कर दीं, और नतीजतन, दिल्ली में FTL सिलेंडर अब लगभग 805.50 रुपए में बिकेंगे। हालांकि, LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बताया कि नए कनेक्शन के लिए FTL सिलेंडर की कीमत बुधवार से लगभग 160 रुपए बढ़ा दी गई है। दिल्ली में नए FTL सिलेंडर कनेक्शन की कीमत अब 1,929.50 रुपए है, जबकि जून में यह 1,765.50 रुपए थी।

काफी कमी

LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप के मैनेजर रंजीत सिंह ने लाइव मिंट की रिपोर्ट में कहा कि हाल के हफ्तों में नए सिलेंडर की बिक्री और FTL रिफिल, दोनों में काफी कमी आई है। उनकी एजेंसी में बिक्री में 40 फीसदी की गिरावट देखी गई है। यह बात इसलिए अहम है क्योंकि 23 मार्च से 22 अप्रैल के बीच लगभग 20 लाख (2 मिलियन) 5kg वाले FTL सिलेंडर बेचे गए थे।

देश में अभी कुल 34 करोड़ (340 मिलियन) घरेलू LPG उपभोक्ता हैं। गौरतलब है कि मार्च की शुरुआत में ग्लोबल सप्लाई की कमी के कारण कमर्शियल LPG सप्लाई रोकने के बाद, सरकार ने 23 मार्च से प्रवासी मजदूरों के लिए FTL सिलेंडर बेचने की इजाजत दी थी।

18 जून को पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा था कि पिछले तीन दिनों में लगभग 1,98,000 FTL सिलेंडर बेचे गए। इसके अलावा, इन सिलेंडरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार और OMC खास कैंप भी लगा रही हैं। मंत्रालय ने 18 जून को बताया कि पिछले तीन दिनों में 1,334 कैंपों के ज़रिए 19,100 से ज़्यादा FTL सिलेंडर बेचे गए।

ऑल-इंडिया LPG डिस्ट्रीब्यूशन फेडरेशन के उत्तर प्रदेश सर्कल के प्रेसिडेंट जगदीश राज ने मीडिया रिपोर्ट में कहा कि कीमतों में भारी बढ़ोतरी की वजह से प्रवासी मजदूरों के बीच FTL सिलेंडर को बढ़ावा देने का मकसद ही खत्म हो गया है। अब हमें रिफिलिंग के लिए कोई ग्राहक नहीं मिलता, क्योंकि अगर प्रति किलो के हिसाब से देखें तो FTL अब 19kg वाले कमर्शियल सिलेंडर से भी महंगा है।

तिरुवनंतपुरम में एक LPG डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा कि उनकी एजेंसी में FTL की कोई नई बिक्री नहीं हो रही है और रिफिल में 20 फीसदी से ज्यादा की कमी आई है। डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा कि अब उपलब्धता कोई समस्या नहीं है। साथ ही, कुछ पेट्रोल पंपों पर छोटे सिलेंडर मिलने से भी LPG एजेंसियों पर मांग पर असर पड़ सकता है। दिल्ली में 19kg वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत अब लगभग 2,930 रुपए है, जो जून में 3,113.50 रुपए थी। इसका मतलब है 154.12 प्रति किलो, जबकि FTL में वही गैस 161.11 रुपए प्रति किलो पड़ती है।

प्रवासी मज़दूरों का असर

मांग में कमी की एक मुख्य वजह प्रवासी मजदूरों- जैसे कि इंडस्ट्रियल वर्कर, स्ट्रीट फूड वेंडर, रेस्टोरेंट में काम करने वाले और सब्जी बेचने वाले-का अपने गृहनगर लौटना है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फ़ॉर माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट के चेयरमैन एस। इरुदया राजन ने मिंट की रिपोर्ट में कहा कि फ्यूल संकट और कीमतों में बढ़ोतरी ने समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया, जिसमें प्रवासी भी शामिल हैं।

राजन ने कहा कि वॉर और सप्लाई की दिक्कतों के कारण कारोबार, दुकानें और अन्य कमर्शियल संस्थान बंद हो गए, जिससे लोगों की नौकरियां चली गईं। हर किसी पर कर्ज का बोझ था और हर कोई प्रभावित हुआ। इसलिए, उन्हें वहां से जाना पड़ा। इसका एक उदाहरण केरल है, जहां युद्ध के दौरान मजदूर और कामगार अपने मूल स्थानों पर लौट गए थे।

गैस की कमी और ऊंची कीमतों ने भी फ्यूल पर निर्भर कारोबारों को प्रभावित किया, जिससे रेस्टोरेंट और खाने-पीने की जगहों सहित कई छोटे कारोबार बंद हो गए। लुधियाना के उद्योगपति और फेडरेशन ऑफ पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बदीश जिंदल ने मीडिया रिपोर्ट में कहा कि युद्ध के समय जो मजदूर चले गए थे, वे अब वापस आने लगे हैं।

जिंदल ने कहा कि लुधियाना में लगभग 85-90 फीसदी इंडस्ट्रियल वर्कर काम पर लौट आए हैं। हालांकि, LPG सिलेंडर रिफिल मिलना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। चूंकि इनमें से ज्यादातर मजदूर प्रवासी हैं, इसलिए कई लोगों को मजबूरन अनऑथराइज्ड रिफिल चैनलों पर निर्भर रहना पड़ता है, जहां उन्हें 19kg सिलेंडर के लिए 3,500 रुपए से 4,000 रुपए तक चुकाने पड़ते हैं।

नया फोन खरीदने का है प्लान तो रुकिए! सरकार दे सकती है बड़ा डिस्काउंट, जीएसटी रेट 5 फीसदी लाने पर विचार

नई दिल्ली, एजेंसी। देश में 25,000 रुपए से कम कीमत वाले स्मार्टफोन पर जीएसटी को घटाकर पांच प्रतिशत करने और अधिक कीमत वाले उपकरणों पर 18 प्रतिशत की मौजूदा दर बनाए रखने का सुझाव दिया गया है। ग्रांट थॉर्नटन (जीटी) भारत और पॉलिसी वॉच इंडिया फाउंडेशन (पीडब्ल्यूआईएफ) ने संयुक्त रूप से तैयार एक रिपोर्ट में बुधवार को यह सुझाव दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि किफायती स्मार्टफोन पर टैक्स ढांचे की समीक्षा की जरूरत है, क्योंकि मौजूदा 18 फीसदी जीएसटी दर अब भारत की डिजिटल इकोनॉमी में स्मार्टफोन की बदलती भूमिका को सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं करती।

अध्ययन के अनुसार, इस तरह के टैक्स स्ट्रक्चर से पहली बार खरीदने वाले और मूल्य-संवेदनशील उपभोक्ताओं के लिए स्मार्टफोन अधिक किफायती हो जाएंगे। साथ ही यह सरकार के डिजिटल इंडिया, वित्तीय समावेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लक्ष्यों को भी समर्थन देगा। इसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया कि एंट्री-लेवल स्मार्टफोन और प्रीमियम डिवाइस पर एक ही GST दर लागू करने से उस सेगमेंट पर ज्यादा असर पड़ता है जो डिजिटल समावेश को बढ़ावा देता है।

क्या कहती है स्टडी?

GT Bharat-PWIF की स्टडी के अनुसार, 25,000 रुपए से कम कीमत वाले स्मार्टफोन का सेगमेंट – जो भारत में हैंडसेट शिपमेंट का लगभग दो-तिहाई हिस्सा है – मुख्य रूप से पहली बार खरीदने वालों, ग्रामीण परिवारों, महिलाओं, छात्रों और कम आय वाले ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करता है। स्टडी में यह भी कहा गया है कि लगभग 35 करोड़ भारतीय अभी भी फीचर फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो यह दिखाता है कि ज्यादा लोगों के डिजिटल दुनिया से जुड़ने में कीमत एक बड़ी बाधा बनी हुई है।

इस बात पर जोर देते हुए कि स्मार्टफोन को अब केवल मनपसंद कंज्यूमर प्रोडक्ट के बजाय डिजिटल दुनिया तक पहुंचने के शुरुआती जरिया के तौर पर देखा जाना चाहिए। पेपर में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली अन्य इकोनॉमीज की तुलना में भारत स्मार्टफोन पर सबसे ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स दरों में से एक लगाता है।

इन देशों में कम लगता है टैक्स

वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों ने अपेक्षाकृत कम टैक्स स्ट्रक्चर अपनाए हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग में कॉम्पिटिटिवनेस बनाए रखते हुए ज्यादा लोगों द्वारा स्मार्टफोन अपनाने में मदद करते हैं। इसमें आगे कहा गया है कि किफायती स्मार्टफोन के लिए अलग GST फ्रेमवर्क को इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए टैक्स में छूट के तौर पर नहीं, बल्कि एक रणनीतिक पॉलिसी कदम के तौर पर देखा जाना चाहिए। यह कदम टैक्स व्यवस्था को भारत के डिजिटल बदलाव, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े लक्ष्यों और लंबे समय के आर्थिक उद्देश्यों के साथ जोड़ता है।

खामेनेई ने जिस जगह ली थी अंतिम सांस, वहीं ले जाया गया शव, उमड़ा जनसैलाब

तेहरान, एजेंसी। पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के शव वाले ताबूत को उस जगह ले जाया गया जहां उनकी हत्या हुई थी। इसकी जानकारी ईरान के सरकारी मीडिया की तरफ से दी गई। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग (IRIB) के मुताबिक, " इसके लिए पहले को कार्यक्रम तय नहीं किया गया था। शहीद नेता अयातुल्ला खामेनेई के शव वाले ताबूत को उनकी शहादत वाली जगह पर लाया गया।" पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का सार्वजनिक विदाई समारोह 4 और 5 जुलाई को होगा। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के मुताबिक, इस सार्वजनिक विदाई में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ शामिल हो सकती है। भीड़ में 2 करोड़ लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। खामेनेई के विदाई समारोह से पहले ईरान सरकार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से फोन पर बात की और शोक जाहिर किया। सोशल मीडिया X पर एक पोस्ट में सरकार ने कहा, "संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने विदेश मंत्री अब्बास अराघची से फोन पर बात की, जिसमें उन्होंने ग्रैंड अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई की शहादत पर शोक जाहिर किया। इसके साथ ही क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना, होर्मुज स्ट्रेट, लेबनान में संघर्ष-विराम और चल रही बातचीत पर चर्चा की।" साथ ही, घाना में ईरान के दूतावास ने 2016 में तेहरान में घाना के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा और खामेनेई के बीच हुई मुलाकात को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी।

भारत ने दिया अफगानिस्तान का साथ तो खुलकर पाकिस्तान के सपोर्ट में उतरा अमेरिका

काबुल के पलटवार को बताया आतंकी हमला

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रुक-रुक कर जारी हिंसक झड़पों के बीच US स्टेट डिपार्टमेंट खुलकर पाकिस्तान के साथ आ गया है।U।S। स्टेट डिपार्टमेंट ने अपने एक बयान में कहा कि 'वह पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी हमले से खुद को बचाने के अधिकार का समर्थन करता है। पाकिस्तानियों को आतंकवादियों के हाथों बहुत नुकसान हुआ है।' फरवरी में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भयंकर संघर्ष छिड़ गया था। 21 फरवरी को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के नंगरहार, पकतीका और खोस्त प्रांतों में हवाई हमले किए। इसके जवाब में अफगान सेना ने भी

पाकिस्तान पर जवाबी हमले शुरू कर दिए। इसके बाद से लगातार अब तक दोनों देशों के बीच हिंसक झड़पें होती रही हैं। यूनाइटेड नेशंस ने सोमवार को कहा कि अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से 27 जून को किए किए गए एयरस्ट्राइक में कम से कम 28 आम लोग मारे गए और 49 घायल हुए। पाकिस्तान की यह कार्रवाई कराची में हुए सिंध रेंजर्स के मुख्यालय पर 3 पाकिस्तानी जवान मारे जाने के बाद की। पाकिस्तान ने इस हमले के लिए तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) से जुड़े गुट 'जमात-उल-अहरार' को जिम्मेदार ठहराया था।

दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर

27 जून के हमले के बाद अफगानिस्तान के तालिबान ने अपने बयान में कहा था कि उन्होंने पाकिस्तानी इलाके में एयरस्ट्राइक की। वहीं, इस्लामाबाद ने कहा कि उसकी सेना ने बलूचिस्तान में चार शुरुआती ड्रोन को रोककर मार गिराया। इसके बाद अफगानिस्तान के तीन प्रांतों पक्तिया, पक्तिका और कुनार में हवाई हमले किए गए। तालिबान के हथियारों और गोला-बारूद के भंडारों को नष्ट किया। फिलहाल, दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। तालिबान ने पाकिस्तान के हमले का बदला लेने की कसम खाई है।

वाशिंगटन ने पाकिस्तान की तरफदारी की

अब वाशिंगटन ने पाकिस्तान के अफगानिस्तान पर हमले की तरफदारी की है। उसने कहा है कि पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी हमले से खुद को बचाने के अधिकार का समर्थन करता है। इसका साफ अर्थ है वाशिंगटन अफगान तालिबान को एक आतंकवादी ग्रुप मानता है। इसके अलावा पाकिस्तान वॉशिंगटन का एक बड़ा नॉन-NATO सहयोगी है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस लौटने के बाद से वॉशिंगटन और इस्लामाबाद के बीच रिश्ते बेहतर हुए हैं। पाकिस्तान ईरान के साथ U।S।-इजराइल युद्ध को सुलझाने की कोशिशों में भी एक बिचौलिया रहा है।

पाकिस्तान अफगानिस्तान पर लगाता रहा है ये आरोप

बता दें कि इस्लामाबाद, अफगानिस्तान पर अक्सर उन मिलिटेंट्स को पनाह देने का आरोप लगाता, जिन्हें वह अपने यहां हुए हमले के लिए जिम्मेदार मानता है। उधर अफगान तालिबान इन आरोपों से इनकार करता है। उसका कहना है कि मिलिटेंसी पाकिस्तान की अंदरूनी समस्या है। पाकिस्तान अपनी सुरक्षा की नाकामियों का दोष दूसरों से हटा रहा है।

हमास अटैक के 1000 दिन : गाजा में तबाही मचाई, जीते-जी मरने जैसी हालत में इजराइल के 26 हजार सैनिक

यरुशलम, एजेंसी। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि युद्ध में घायल सैनिकों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि उनके पुनर्वास का पूरा सिस्टम जल्द ही टूट सकता है। 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले के बाद अब तक 26,200 IDF सैनिक और सुरक्षा कर्मी घायल हो चुके हैं। इनमें से 65% सैनिकों को मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से गुजरना पड़ रहा है। जैसे PTSD (ट्रॉमा), चिंता, डिप्रेशन और सिविलियन जीवन में वापस लौटने में दिक्कत आदि। मंत्रालय का अनुमान है कि2026 तक कुल घायल सैनिकों की संख्या 90,000 से ज्यादा हो जाएगी।

2028 तक ये संख्या 1 लाख के करीब पहुंच जाएगी। इनमें से लगभग आधे लोग मनोवैज्ञानिक समस्याओं से जूझ सकते हैं। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, 7 अक्टूबर के बाद से घायल

हुए लोगों में से लगभग 17,000 लोग मनोवैज्ञानिक चोटों से जूझ रहे हैं। इनमें से 7,700 लोगों को शारीरिक चोटें भी आई हैं, जबकि लगभग 9,000 लोगों का इलाज सिर्फ शारीरिक चोटों के लिए किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल अमीर बारम ने चेतावनी दी है कि पब्लिक कमिटी की सिफारिशों को लागू न करना 'कोई विकल्प नहीं है'। कमिटी के प्रस्तावों में रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट का बजट बढ़ाना, हर घायल पूर्व सैनिक के लिए एक खास पर्सनल केस मैनेजर नियुक्त करना और मनोवैज्ञानिक इलाज के विकल्पों का विस्तार करना शामिल था।

बाराम ने बताया कि रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री दोनों ने ही समिति के निष्कर्षों का स्वागत किया है। बाराम ने कहा, "हम सभी को नतीजों और उन्हें लागू करने के आधार पर आंका जाएगा, न कि बयानों के आधार पर।" उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो "युद्ध में घायल हुए लोगों के पुनर्वास का यह संवेदनशील राष्ट्रीय तंत्र, जो एक पवित्र काम कर रहा है, बोझ तले ढह सकता है।"

मरीजों में 92 प्रतिशत हैं पुरुष

मरीजों में 92 प्रतिशत पुरुष और 8 प्रतिशत महिलाएं हैं और नए मरीजों में से लगभग आधे 30 साल से कम उम्र के हैं। युद्ध के दौरान रिहैबिलिटेशन डिवीजन ने अपनी मदद का दायरा काफी बढ़ाया है। इसने अपने मेंटल हेल्थ स्टाफ की संख्या को चार गुना बढ़ाकर लगभग 4,000 प्रोफेशनल्स कर दिया है और रिहैबिलिटेशन होम्स की संख्या को तीन गुना कर दिया है। मंत्रालय ने देश भर में नौ रिहैबिलिटेशन फार्म, एक मोबाइल मेंटल हेल्थ क्राइसिस यूनिट और युवा मरीजों के लिए एक डेडिकेटेड नर्सिंग डिपार्टमेंट भी बनाया है, हालांकि उसका कहना है कि जरूरत के पैमाने को देखते हुए अभी भी एक व्यापक राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की जरूरत है।

ईरान जंग के बाद बदल रहा दुबई, यूएई में अपना दबदबा कैसे बढ़ा रहे हैं भारतीय

यरुशलम, एजेंसी। दुबई लंबे समय से भारतीयों के लिए नौकरी और कारोबार का बड़ा केंद्र रहा है, लेकिन अब तस्वीर तेजी से बदल रही है। पहले जहां भारतीय दुबई में काम करने या बिजनेस शुरू करने जाते थे, वहीं अब बड़ी संख्या में वहां घर और जमीन खरीद रहे हैं। पिछले कुछ सालों में दुबई का रियल एस्टेट बाजार लगातार तेजी से बढ़ा, लेकिन अब पांच साल की रिकॉर्ड रैली के बाद बाजार में थोड़ी नरमी आने लगी है।

इसी बीच ईरान-इजराइल तनाव और पश्चिम एशिया में बढ़ती अनिश्चितता ने इनवेस्टर्स की रणनीति बदल दी है। ऐसे समय में भारतीय इनवेस्टर्स ने इसे मौका मानते हुए दुबई की प्रॉपर्टी में निवेश बढ़ा दिया है। कम टैक्स, बेहतर रिटर्न, मजबूत कानूनी व्यवस्था और गोल्डन वीजा जैसी सुविधाएं भी भारतीयों को अट्रैक्ट कर रही हैं।

आज भारतीय सिर्फ दुबई में घर खरीदने वाले विदेशी नागरिक नहीं रह गए हैं, बल्कि वे वहां के सबसे बड़े विदेशी प्रॉपर्टी खरीदार बन चुके हैं। माना जा रहा है कि अगर यही रफ्तार जारी रही तो आने वाले सालों में दुबई के प्रॉपर्टी बाजार पर भारतीयों का आर्थिक प्रभाव और मजबूत होगा।

अलग-अलग रिपोर्टें बताती हैं कि विदेशी खरीदारों में भारतीय सबसे आगे हैं और हर साल अरबों डॉलर का निवेश कर रहे हैं। इससे भारतीय निवेशकों की आर्थिक ताकत के साथ-साथ यूएई में उनकी मौजूदगी भी लगातार बढ़ रही है।

5 बड़ी बातें

भारतीय लगातार दूसरे साल दुबई में सबसे बड़े विदेशी प्रॉपर्टी खरीदार बने हैं।

पांच साल की तेजी के बाद दुबई के प्रॉपर्टी बाजार में कीमतों की रफ्तार धीमी पड़ रही है।

ईरान-इजराइल तनाव के बीच कई निवेशकों ने सुरक्षित निवेश के तौर पर दुबई को चुना है।

गोल्डन वीजा और टैक्स में राहत भारतीय निवेशकों को आकर्षित कर रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले सालों में भारतीयों का निवेश और बढ़ सकता है।

क्यों ठंडा पड़ रहा है दुबई का प्रॉपर्टी बाजार?

रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले पांच सालों में दुबई के प्रॉपर्टी बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। इस दौरान कई इलाकों में घरों की कीमतें रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गईं। अब बाजार में नए प्रोजेक्ट्स तेजी से आ रहे हैं, जिससे सप्लाई बढ़ रही है। इसी वजह से कीमतों में पहले जैसी तेज बढ़ोतरी नहीं हो रही। कई जगहों पर खरीदारों के लिए बेहतर डील भी मिलने लगी है।

अन्ना हजारे के भूख हड़ताल से पहले महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, RTI नियमों में बदलाव पर लगाई रोक

मुंबई, एजेंसी। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के ऐलान के बाद, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सूचना का अधिकार (RTI) नियमों में किए गए कई विवादित बदलावों पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया है। इससे पहले पिछले महीने हजारे ने चेतावनी दी थी कि अगर राज्य सरकार ने RTI नियमों में किए गए संशोधनों को तुरंत वापस नहीं लिया, तो वह 5 जुलाई से अहिल्यानगर जिले के रालेगण सिद्धि गांव में भूख हड़ताल शुरू करेंगे।

महाराष्ट्र सूचना का अधिकार नियम, 2026 में कई अहम बदलावों का प्रस्ताव किया गया था, जिसमें अधिक एप्लीकेशन फीस, पहचान का सबूत देना अनिवार्य किए जाने के अलावा एक यह शर्त भी शामिल था कि हर आवेदन में सिर्फ एक ही विषय पर जानकारी मांगी जाए। लेकिन सीएम फडणवीस ने कल गुरुवार को RTI के मुख्य आयुक्त से नए नोटिफाई किए गए नियमों पर रोक लगाने का निर्देश दिया।

बदलाव के खिलाफ हजारे की हड़ताल

कानून में संशोधन से नाराज अन्ना हजारे ने फडणवीस सरकार से इन नियमों को वापस लेने की अपील की थी। उनका आरोप था कि ये संशोधन RTI एक्ट की मूल भावना को कमजोर करते हैं और नागरिकों के लिए सरकारी जानकारी पाने की प्रक्रिया को और मुश्किल बना देते हैं। साथ ही उन्होंने धमकी दी थी कि अगर RTI नियमों में किए जा रहे बदलाव वापस नहीं लिए गए, तो वे 5 जुलाई से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री फडणवीस को भेजे गए एक पत्र में अन्ना हजारे ने कहा कि नए नियमों से प्रक्रिया में रुकावटें आती हैं, खर्च बढ़ती है और अपील की प्रक्रिया में जटिलताएं पैदा होती हैं, जिससे जवाबदेही कमजोर होती है। साथ ही उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि ये नियम जनता से सलाह-मशविरा किए बिना बनाए गए थे। उन्होंने सरकार से मांग की कि इन्हें तुरंत रद्द किया जाए और RTI एक्सपर्ट, सूचना आयुक्तों, सोशल एक्टिविस्ट, वकीलों, पत्रकारों और नागरिकों से सलाह-मशविरा करके नए नियम बनाए जाएं।

किस तरह के अहम बदलाव किए गए

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी और 12 जून को सरकारी गजट में प्रकाशित नोटिफिकेशन के अनुसार, नए नियम प्रकाशित होते ही तुरंत लागू हो गए। नए नियमों के तहत, RTI एक्ट के तहत जानकारी मांगने वाले हर आवेदकों को 730 रुपये की एप्लीकेशन फीस देनी होगी। नियमों में यह प्रावधान भी किया गया है कि RTI आवेदन करने के दौरान आम तौर पर मुद्दा एक ही विषय तक सीमित रहे। साथ ही शब्दों की सीमा भी तय की गई थी और यह 150 शब्द से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर कई विषय शामिल होते हैं, तो PIO सिर्फ पहले विषय पर कार्रवाई कर सकता है और आवेदक को शेष अन्य मुद्दों के लिए अलग-अलग आवेदन दाखिल करने की सलाह दे सकता है।

एक छूट क्या मिली पूरा बिजनेस खड़ा हो गया... मोर के पंख को लेकर कानून में 'लूप'

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की वरिष्ठ नेता और पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी ने देश के वन्यजीव संरक्षण कानूनों में दी गई छूट पर फिर से विचार करने की मांग की है। उन्होंने कानूनों में उन खामियों को लेकर गहरी चिंता जताई जिनसे राष्ट्रीय पक्षी मोर के अवैध शिकार को बढ़ावा मिल सकता है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि मोर को भी जिंदा रहने का हक है, और उसे भी जीने का मौका मिलना चाहिए।

नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान मेनका गांधी ने कल गुरुवार को मौजूदा नियमों की आलोचना की और कहा कि इनसे मोर के पंखों के कमर्शियल इस्तेमाल को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, जानवरों की भलाई और सामाजिक जिम्मेदारी को आपस में जुड़ा मुद्दा बताया और कहा कि ये "एक ही सोच के अलग-अलग रूप" हैं।

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने इस मुद्दे की जड़ 1972 के वन्यजीव संरक्षण कानून (Wildlife Protection Act of 1972) में बताई, जिसमें दिगंबर संप्रदाय के जैन साधुओं को 'पिच्छी' (झड़े हुए मोर के पंखों से बना छोटा सा ब्रश) के लिए मोर के पंखों का इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई थी। हालांकि, उन्होंने आगाह भी किया कि इस छूट के कई अनचाहे नतीजे भी निकले हैं। मेनका गांधी ने कहा, "वह छूट दी गई थी। लेकिन एक बार जब दरवाजा खुला, तो इसके आस-पास एक पूरा उद्योग ही खड़ा हो गया।" उन्होंने इस बात को गलत बताया कि बाजार की मांग पूरी करने के लिए मोर से प्राकृतिक रूप से भारी मात्रा में पंख मिल जाते हैं। उन्होंने कहा कि कमर्शियल मांग की वजह से ही सीधे तौर पर अवैध शिकार को बढ़ावा दिया गया। नियम में बदलाव की बात करते हुए मेनका ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान इस कमी को दूर करने के लिए कानूनी संशोधन करवाने की कोशिश की थी, लेकिन वह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सका। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी आलोचना किसी खास समुदाय को लेकर नहीं है, बल्कि इस बात पर है कि कैसे कानून से मिले कुछ छूटों का गलत इस्तेमाल हो सकता है।

जैन समूहों के विरोध और कानूनी नोटिसों का जवाब देते हुए मेनका गांधी अपनी बात पर अड़ी रहीं और उन्होंने जानवरों की भलाई के आधार पर चुनौती दी गई अन्य पारंपरिक प्रथाओं का उदाहरण दिया। बीजेपी नेता ने कोविड-19 महामारी के दौरान केरल के मलप्पुरम की एक घटना का जिक्र किया, जिसमें फलों के अंदर छिपाकर विस्फोटक रखे जाते थे और फिर इसकी वजह से हाथी घायल हो जाते थे। उन्होंने निराशा जताते हुए कहा, "हाथी जब उन फलों को खा लेते थे, तो इस दौरान मुंह के अंदर धमाकों की वजह से उनके जबड़े टूट जाते थे। इस पर उनका कहना था कि "यह हमारा रिवाज है।' क्या बम लगाना और जानवरों के जबड़े तोड़ना हमारी परंपरा है?"

जब आयुष्मान के थिएटर ग्रुप ने वामिका गब्बी को कर दिया था रिजेक्ट, एक्ट्रेस ने साझा किया मजेदार किस्सा

आयुष्मान खुराना और वामिका गब्बी हाल ही में रकुल प्रीत सिंह और सारा अली खान के साथ 'पति पत्नी और वो 2' में नजर आए थे। पिछले महीने फिल्म प्रमोशन के दौरान वामिका गब्बी ने आयुष्मान से जुड़ा एक किस्सा भी साझा किया था। जिसमें वामिका ने बताया था कि आयुष्मान खुराना के एक थिएटर ग्रुप ने उन्हें एक बार रिजेक्ट कर दिया था। 'पति पत्नी और वो दो' के प्रमोशन के दौरान वामिका गब्बी और आयुष्मान खुराना फिल्म की बाकी कास्ट के साथ एक कॉमेडी शो पर पहुंचे थे। जहां बातचीत के दौरान शो में आयुष्मान ने फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले चंडीगढ़ में अपने कॉलेज के दिनों के बारे में बात की और बताया कि कैसे वह तब से ही एक्टिंग और सिंगिंग में बहुत ज्यादा शामिल थे।

उन्होंने कहा, 'मेरा एक बैंड और एक थिएटर ग्रुप था, मैं चंडीगढ़ में बहुत मजा कर रहा था।' वामिका ने उनकी बात बीच में काटते हुए पूछा, 'यह कौन सा थिएटर ग्रुप था? आगाज?' फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने उस थिएटर ग्रुप के लिए ऑडिशन दिया था।

वामिका ने कहा, 'उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था।' थोड़ा शर्मिंदा होते हुए आयुष्मान ने जवाब दिया, 'मैं उस समय वहां नहीं था। जरूर मेरे जूनियर्स ने ही आपको रिजेक्ट किया होगा।' वामिका ने तंज कसते हुए कहा, 'हां। लेकिन अब हम साथ में एक फिल्म कर रहे हैं, तो भाड़ में जाओ।' बाद में उन्होंने साफ किया, 'मैं यह बात तुम्हारे जूनियर्स से कह रही हूं, तुमसे नहीं।'

'पति पत्नी और वो 2' का निर्देशन मुदस्सर अजीज ने किया था। यह फिल्म 2019 की फिल्म 'पति पत्नी और वो' का स्पिरिचुअल सीक्वल थी, जिसमें कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे मुख्य भूमिकाओं में थे। यह फिल्म मई में सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी, जिसे क्रिटिक्स और दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली और बॉक्स ऑफिस पर भी इसका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा।

वर्कफ्रंट की बात करें तो आयुष्मान और वामिका दोनों के पास कई फिल्में हैं जो जल्द ही आने वाली हैं। आयुष्मान अगली बार आकाश ए. कौशिक की फिल्म 'उड़ता तीर' में नजर आएंगे, जिसमें सारा अली खान भी हैं। इसके अलावा उनकी आने वाली फिल्मों में 'ये प्रेम मोल लिया' और 'मुपापा' भी शामिल हैं। वहीं, वामिका के पास भी कई भाषाओं में कई प्रोजेक्ट्स हैं। वह तमिल फिल्मों 'इरावकालम', 'जिनी' और 'डीसी' में नजर आएंगी। उनकी अगली तेलुगु फिल्म 'G2' है। उनके पास मलयालम और पंजाबी फिल्में 'टिकी टाका' और 'किकली' भी हैं। उनकी आने वाली हिंदी फिल्मों में राजकुमार राव की 'प्रहार – द उज्ज्वल निकम स्टोरी', 'दिल का दरवाजा खोल ना डार्लिंग' और 'कुकु की कुंडली' शामिल हैं।

धूप से बचाया, हर थोड़ी देर में मिला ब्रेक, प्रेग्नेंसी में समांथा ने ऐसे शूट की थी 'मां इंटी बंगारम'

साउथ एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु इन दिनों अपने प्रेगनेंसी फेज को एंजॉय कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म किया है। इस बीच उनकी फिल्म 'मा इंटी बंगारम' की डायरेक्टर नंदिनी रेड्डी ने खुलासा किया है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान एक्ट्रेस प्रेगनेंट थी।

साउथ एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु इन दिनों अपना प्रेगनेंसी को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। एक्ट्रेस कुछ समय पहले ही प्रेगनेंसी का ऐलान किया है और इस फेस को काफी एंजॉय भी कर रही हैं। वहीं कुछ समय पहले ही एक्ट्रेस की फिल्म 'मा इंटी बंगारम' सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद भी किया है। अब फिल्म के डायरेक्टर ने नंदिनी रेड्डी ने बताया है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान समांथा प्रेगनेंट की। लेकिन फिर भी उन्होंने फिल्म की शूटिंग पूरी की।

नंदिनी ने खुलासा किया कि उन्होंने इस दौरान एक्शन सीन तक शूट किए हैं। नंदिनी ने यह भी बताया कि शूटिंग के दौरान समांथा और उनके होने वाले बच्चे की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया। फिल्म की टीम ने हर जरूरी सावधानी बरती, ताकि शूटिंग सुरक्षित और आरामदायक माहौल में पूरी हो सके।

प्रेगनेंसी में समांथा ने शूट की थी फिल्म

निर्देशक नंदिनी रेड्डी ने बताया कि 'मा इंटी बंगारम' की शूटिंग नवंबर 2025 में शुरू हुई थी और फिल्म की शूटिंग पूरी होने में करीब 6 से 7 महीने लगे। पूरी फिल्म की शूटिंग लगभग 54 दिनों में पूरी की गई। उन्होंने कहा कि जब उन्हें पता चला कि सामंथा प्रेगनेंट हैं, तब तक फिल्म के ज्यादातर एक्शन सीन शूट हो चुके थे। नंदिनी ने बताया, "जब हमें सामंथा की प्रेगनेंसी के बारे में पता चला, तब हम फिल्म के आखिरी हिस्से की शूटिंग कर रहे थे। उस समय 'थस्साडिया' गाने की शूटिंग चल रही थी।" उन्होंने आगे बताया कि उस गाने में समांथा को एनर्जेटिक डांस स्टेप्स करने थे और एक कार चेज़ सीन भी शूट होना बाकी था, क्योंकि ये सीन खुले में शूट किए जाने थे, इसलिए पूरी टीम ने समांथा की सेहत का खास ध्यान रखा।

समांथा का रखा गया पूरा ध्यान

नंदिनी के बताया कि, "हमने ध्यान रखा कि समांथा पर ज्यादा शारीरिक दबाव न पड़े। उन्हें बीच-बीच में पूरा आराम दिया गया। शूटिंग तेज धूप में नहीं की गई, क्योंकि उस समय गर्मियां शुरू हो रही थीं। हमने हर जरूरी सावधानी बरती ताकि वह ज्यादा थकान महसूस न करें और शूटिंग आराम से पूरी हो सके।"

समांथा को लेकर कही ये बात

निर्देशक नंदिनी रेड्डी ने सामंथा रुथ प्रभु की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सामंथा हर मायने में एक सुपरस्टार हैं। उनकी एक्टिंग, कॉमिक टाइमिंग, इमोशनल सीन, एक्शन और डांस हर चीज में उनका शानदार प्रदर्शन देखने को मिलता है। इसलिए हमने इस फिल्म में उनका हर रंग दिखाने की कोशिश की है। बता दें समांथा की फिल्म 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसे दर्शकों का मिलाजुला रिस्पॉन्स मिला है।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित। शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com
*सम्पादक: प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com